सांध्य दैनिक

नई दृष्टिबिंदु

सच की शक्ति, जनता की दृष्टि

PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

वर्ष–01 अंक–18 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, गुरुवार 05 फरवरी 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य –2 रुपए,

सु-विचार

किसी के साथ बैठना बहुत आसान है... ।
परंतु, खड़े रहना बहुत ही कठिन
....अज्ञात

आईआईटी भिलाई के वैज्ञानिकों ने प्रदूषित पानी को साफ करने के लिए पर्यावरण–अनुकूल सामग्री विकसित की

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

औद्योगिक कचरे के कारण पानी का प्रदूषण भारत में एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है, जिससे साफ और सुरक्षित पानी तक पहुँच दिन–प्रतिदिन कठिन होती जा रही है। जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के समर्थन में, आईआईटी भिलाई के वैज्ञानिकों ने एक नई पर्यावरण–अनुकूल सामग्री विकसित की है, जो दूषित पानी से हानिकारक प्रदूषकों को हटाने में मदद कर सकती है।

कौशिक माहात, निशिकांत सिंह, दुर्गेश कुमार सिन्हा, स्वरूप मैती और डॉ. संजीब बेनार्जी की शोध टीम ने यह अमीनो अम्ल–आधारित हाइड्रोजेल तैयार किया है। इस सामग्री की खास बात यह है कि यह कमरे के तापमान पर अपने–आप बन जाती है और इसमें किसी भी हानिकारक रसायन या उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती। इससे यह प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, सरल और टिकाऊ बनती है।

यह हाइड्रोजेल स्पंज जैसी संरचना वाला होता है, जिससे यह औद्योगिक अपशिष्ट जल में मौजूद जहरीले रंगों को आसानी से सोख लेता है। इसका परीक्षण न केवल प्रयोगशाला में किया गया, बल्कि वास्तविक रूप से प्रदूषित नदी के पानी में भी किया गया, जहाँ इसने बेहतरीन परिणाम दिखाए। यह सामग्री कई बार इस्तेमाल की जा सकती है, विभिन्न आकारों में ढाली जा सकती है और उपयोग के बाद प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाती है, जिससे आगे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता।

इस शोध का नेतृत्व करने वाले डॉ. संजीब बेनार्जी ने कहा कि 'आज पानी को साफ करने वाली कई सामग्री ऐसे रसायनों से बनी होती हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचा सकती हैं। हमारा शोध यह दिखाता है कि प्राकृतिक स्रोतों से बनी सामग्री भी पानी को प्रभावी ढंग से साफ कर सकती हैं और बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए सुरक्षित हैं।'

मुख्य लाभ

- प्रदूषित पानी की सफाई : अपशिष्ट जल से हानिकारक कार्बनिक प्रदूषकों को हटाती है
- पर्यावरण–अनुकूल : प्राकृतिक सामग्री से बनी, बिना जहरीले रसायनों के
- वास्तविक उपयोग में सफल : प्रदूषित नदी के पानी में प्रभावी और बार–बार उपयोग योग्य
- पर्यावरण के लिए सुरक्षित : जैव–अपघटनीय हाइड्रोजेल लंबे समय तक पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाते

पर्यावरण–अनुकूल डिजाइन और मजबूत जल–शोधन क्षमता के साथ, यह नई सामग्री भविष्य में अपशिष्ट जल उपचार के लिए एक उम्मीदभरा समाधान प्रस्तुत करती है, विशेष रूप से औद्योगिक प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्रों के लिए। यह शोध भारत के स्वच्छ जल, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लक्ष्यों को मजबूत करता है। यह शोध कार्य विश्व–प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय पत्रिका Advanced Functional Materials (Wiley-VCH) में प्रकाशित हुआ है, जो पर्यावरणीय स्थिरता के लिए उन्नत सामग्री अनुसंधान में आईआईटी भिलाई के बढ़ते योगदान को दर्शाता है।

त्वरित टिप्पणी

ममता बनर्जी की हुंकार, नरेन्द्र मोदी-शाह को खुली चुनौती

आलोक तिवारी / नईदिल्ली

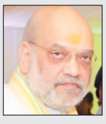

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर सियासी मैदान में नई लकीर खींच दी है। चुनाव से पहले जिस आक्रामक तेवर में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को खुली चुनौती दी है, उसने देश की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है।

ममता ने सिर्फ भाजपा पर हमला नहीं बोला, बल्कि चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाकर लोकतंत्र को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है। मौजूदा दौर में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठते सवालों को ममता ने राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है, जो विपक्ष को एक नया हथियार देता नजर आ रहा है।

अब बंगाल की राजनीति में मुकाबला साफ तौर पर ह्लममता बनाम मोदी–शाहह्व बन चुका है। कांग्रेस और वाम दल हाशिए पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। कभी जिन लेफ्ट और कांग्रेस की जड़ों को उखाड़कर ममता ने तृणमूल कांग्रेस की नींव रखी थी, आज वही दल बंगाल की राजनीति में असरहीन नजर आते हैं।

यह भी याद रखना होगा कि पिछली बार तमाम राजनीतिक दबाव, केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता और विपक्षी रणनीतियों के बावजूद ममता ने सत्ता बचाकर दिखाया था। भले ही वह अपनी सीट शुभेंदु अधिकारी से हार गई थीं, लेकिन पूरे राज्य में भाजपा के विजय रथ को रोकने में सफल रहीं।

ममता की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि वह संघर्ष को अपनी राजनीतिक पहचान बनाती हैं। वह खुद को ह्ललड़ने वाली नेताह्व के रूप में पेश करती हैं और जनता में यह संदेश देती हैं कि वह दिल्ली की सत्ता के सामने झुकने वाली नहीं हैं।

आज की सियासत में ममता सिर्फ बंगाल की नेता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विपक्ष की एक मजबूत आवाज बनकर उभरी हैं। उनका आक्रामक रुख साफ संकेत देता है कि आने वाले चुनावों में वह भाजपा को हर मोर्चे पर घेरने की रणनीति पर काम कर रही हैं।

अब सवाल यही है कि क्या ममता की यह हुंकार बंगाल तक सीमित रहेगी या राष्ट्रीय राजनीति में भी नया समीकरण गढ़ेगी? इसका जवाब आने वाले चुनावी नतीजे ही देंगे।

ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट में, SIR प्रक्रिया के विरोध में दी अपना पक्ष–लोकतंत्र बचाने की दलील

संदीप सिंह / नईदिल्ली

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत के सवोच्च न्यायालय (Supreme Court) में स्वयं उपस्थित होकर विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision — SIR) प्रक्रिया के खिलाफ दलील दी। यह शायद पहली बार है जब कोई राज्य की कार्यरत मुख्यमंत्री सीधे सुप्रीम कोर्ट की पीठ के सामने अपनी याचिका पर बहस करने पहुँची हैं।

SIR को चुनौती: 'बंगाल को लक्ष्य बनाया जा रहा है'

मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग (ECI) द्वारा बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को असंवैधानिक बताया और इसे रद्द करने की गुहार लगाई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया केवल पश्चिम बंगाल में लागू कर बंगाल के मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि असम जैसे अन्य राज्यों में इसी तरह का SIR नहीं चलाया जा रहा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह सिर्फ तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक आधार पर लोगों के अधिकारों पर हमला है। केवल बंगाल का चयन क्यों?

उन्होंने यह भी कहा कि SIR के नाम पर मतदाता सूची में 'तार्किक विसंगति' के कारण नाम काटे जा रहे हैं — जिनमें शादी के बाद उपनाम बदलने वाली महिलाएं, घर बदलने वाले लोग और वास्तविक नागरिक शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने ECI को नोटिस जारी किया

मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत की पीठ ने उनकी दलीलों को गंभीरता से लिया और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने चुनाव आयोग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि किसी भी वास्तविक नागरिक का नाम मतदाता सूची से न हटाया जाए।

यह कदम बंगाल के मतदाताओं के अधिकारों और संविधान के मूल सिद्धांतों की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अगली सुनवाई 9 फरवरी 2026 को

CJI की पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी 2026 (सोमवार) तय की है। उस दिन मुख्यमंत्री के दुबारा सुप्रीम कोर्ट में पेश होने की संभावना है, जहाँ कोर्ट आगे की प्रक्रिया और SIR के वैधानिक अधिकारों पर विस्तृत सुनवाई करेगी।

राजनीतिक संदेशः यह सिर्फ अदालत नहीं, लोकतंत्र की कसौटी है ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में मौजूद अधिकारियों और मीडिया के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि यह याचिका केवल चुनावी तकनीकी मुद्दा नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों, मतदाता पहचान और संघीय संरचना की जड़ पर सवाल है। उनका कहना था कि जब लोकतंत्र के आधार पर सवाल उठते हैं, तो केवल वकील या नेता के रूप में नहीं, बल्कि जनता के रूप में भी आवाज उठानी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ममता का यह कदम न केवल कानूनी आधार पर बल्कि राजनीतिक रूप से भी एक बड़ा संदेश है—जहाँ चुनाव आयोग और न्यायपालिका के समीकरण बदल रहे हैं, वहाँ सियासी नेतृत्व सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा रहा है।

न्याय में देरी का आरोप, अदालत में भावुक दलील

ममता बनर्जी ने कोर्ट में घोषणा की कि न्याय व्यवस्था 'बंद दरवाजों के पीछे रो रही है।' उन्होंने बताया कि उनके वकील शुरू से ही मामले पर लड़ रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया बेहद धीमी और पक्षपाती लग रही है, जिससे उन्हें स्वयं कोर्ट में आकर दलील देने का निर्णय लेना पड़ा।

इसके साथ ही उन्होंने SIR प्रक्रिया को जन–विरोधी बताया और कहा कि इससे न केवल मतदाता सूची प्रभावित हुई है, बल्कि मानवीय और प्रशासनिक संकट भी उभरा है।

प्रशिक्षित अधिवक्ता के रूप में सीधी बहस

अधिकांश लोगों को यह नहीं पता कि ममता बनर्जी एक प्रशिक्षित अधिवक्ता (trained advocate) भी हैं। उन्होंने interlocutory application दाखिल कर खुद बहस करने की अनुमति मांगी, ताकि वे न केवल कानूनी बिंदुओं को बल्कि जमीनी अनुभव और समस्याओं को भी सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रत्यक्ष रख सकें।

150 से अधिक मौतें, सूची प्रक्रिया पर भारी दबाव

मुख्यमंत्री ने अदालत में दावा किया कि SIR की वजह से उत्पन्न दबाव के चलते राज्य में 150 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें एक बूथ स्तर का अधिकारी (BLO) भी शामिल है, जिसने तनाव के कारण आत्महत्या कर ली। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक याचिका नहीं, यह लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है।

कवासी लखमा की जमानत सत्य की जीत - कांग्रेस

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधायक कवासी लखमा को अंततः सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलना स्वागत योग्य है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि एक बार फिर सत्य की जीत हुई है और यह साबित हो गया कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं।

कवासी लखमा को भाजपा की केंद्र एवं राज्य सरकार ने षडयंत्र पूर्वक कथित शराब घोटाले में फसाया था। एक वरिष्ठ आदिवासी नेता को जेल में बंद राजनीतिक विद्वेष के कारण किया गया था, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है। कांग्रेस पार्टी अदालत के फैसले का स्वागत करती है। पूरा भरोसा है जब इस मामले का अंतिम फैसला आएगा वे बाईज्जत बरी भी होंगे।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तब भाजपा की केन्द्र सरकार और ईडी के साथ मिलीभगत करके इस शराब घोटाले की पटकथा लिखा था।

जैसे ही भाजपा की राज्य में सरकार आयी ईओडब्लू के माध्यम से इस पटकथा को आगे बढ़ाया गया। शराब घोटाले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। ईओडब्ल्यू कांग्रेस को बदनाम करने के लिये इस प्रकार की कवायद कर रही है। वास्तव में ईओडब्लू में साहस है वर्तमान सरकार ने जो शराब नीति में परिवर्तन किया है। जिससे सरकार सीधे शराब निर्माताओं कंपनियों से शराब खरीदी करेगी। इस मामले की जांच करे, कि कमीशन का पैसा कहां जाएगा?

गड़बड़ी

निजी अस्पताल की दवा दुकान से दवा लेना अनिवार्य नहीं, लेकिन जमीनी अमल पर सवाल

अस्पष्ट पर्ची, दवा-कमीशन और बोर्ड आदेश के बीच फंसी मरीजों की हकीकत

नरेश डाकलिया / रायपुर–राजनांदगांव

निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों को अपनी ही दवा दुकानों से दवा लेने के लिए मजबूर किए जाने की शिकायतों पर शासन ने बड़ा आदेश जारी किया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी निजी अस्पताल की फार्मेसी से दवा लेना मरीज के लिए अनिवार्य नहीं है और मरीज किसी भी अधिकृत दवा दुकान से दवा खरीदने के लिए स्वतंत्र है।

पत्र क्रमांक एवं दिनांक का हवाला देते हुए शासन ने निर्देश दिया है कि राज्य के सभी निजी अस्पतालों में एक स्पष्ट सूचना पटल (बोर्ड) अनिवार्य रूप से लगाया जाए, जिसमें साफ शब्दों में यह लिखा हो कि 'मरीज अस्पताल की फार्मेसी से दवा लेने के लिए बाध्य नहीं है।'

इस आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी औषधि निरीक्षकों एवं संबंधित अधिकारियों को सौंपी गई है। लेकिन असली सवालः आदेश लागू कैसे होगा? स्वास्थ्य अधिकारों से जुड़े जानकारों का कहना है कि यह आदेश तब तक प्रभावी नहीं हो सकता, जब तक डॉक्टर स्वयं साफ, स्पष्ट और बिना घसीटी हैंडराइटिंग में दवा की पर्ची नहीं लिखेंगे। वर्तमान में अधिकांश पर्चियां इतनी अस्पष्ट होती हैं कि मरीज बाहर की दवा दुकान से दवा लेने में असहज महसूस करता है और अंततः अस्पताल की फार्मेसी पर निर्भर हो जाता है।

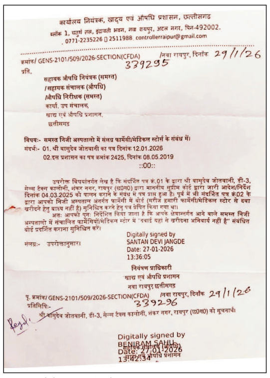

कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़
ब्लॉक 1, चतुर्थ तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन-492002.
0771-2235226 2511988 controllerraipur@gmail.com

क्रमांक/ GENS-2101/509/2026-SECTION(CFDA) 339295 /नवा रायपुर, दिनांक 29/1/26

प्रति,
सहायक औषधि नियंत्रक (समस्त)
/सहायक संचालक (औषधि)
/औषधि निरीक्षक (समस्त)
कार्या. उप संचालक,
खाद्य एवं औषधि प्रशासन,
छत्तीसगढ़

विषयः- समस्त निजी अस्पतालो में संलग्न फार्मेसी/मेडिकल स्टोर्स के संबंध में।
संदर्भः- 01. श्री वासुदेव जोतवानी का पत्र दिनांक 12.01.2026
02. इस प्रशासन का पत्र क्रमांक 2425, दिनांक 08.05.2019
::00::

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र क्रं.01 के द्वारा श्री वासुदेव जोतवानी, डी-3, सेल्स टैक्स कालोनी, शंकर नगर, रायपुर (छ0ग0) द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश/निर्देश दिनांक 04.03.2025 को पालन कराने के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है। पूर्व में भी संदर्भित पत्र क्र.02 के द्वारा आपको निजी अस्पताल अंतर्गत फार्मेसी में बोर्ड (मरीज हमारी फार्मेसी/मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने हेतु बाध्य नहीं है) सुनिश्चित करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त निजी अस्पतालो में संचालित फार्मेसियों/मेडिकल स्टोर में "दवाई यहां से खरीदना अनिवार्य नहीं है" संबंधित बोर्ड प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
SANTAN DEVI JANGDE
Date: 27-01-2026
13:36:05
नियंत्रण प्राधिकारी
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
नवा रायपुर छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/ GENS-2101/509/2026-SECTION(CFDA) 339296 /नवा रायपुर, दिनांक 29/1/26
प्रतिलिपिः-
श्री वासुदेव जोतवानी, डी-3, सेल्स टैक्स कालोनी, शंकर नगर, रायपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ।

Digitally signed by
BENIRAM SAHU
Date: 27-01-2026
13:42:34

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला

रायपुर निवासी वासुदेव जेतवानी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए सरकार से यह आग्रह किया गया था कि निजी अस्पतालों में इस तरह की बाध्यता समाप्त की जाए। शिकायतों को गंभीर मानते हुए शासन ने यह आदेश जारी किया, जिसे स्वास्थ्य विभाग एक बड़ी उपलब्धि बता रहा है।

दवा-कमीशन की सच्चाई भी आई सामने

इस पूरे मामले में एक संवेदनशील लेकिन अहम सवाल भी उठ रहा है। जानकारों के अनुसार, कई मामलों में डॉक्टरों को हर दवा या विशेष ब्रांड लिखने पर आर्थिक लाभ (कमीशन) मिलता है। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या डॉक्टर स्वेच्छा से अपनी इस अतिरिक्त आय को समाप्त करना चाहेंगे?

यही कारण बताया जा रहा है कि आदेशों के बावजूद जमीनी स्तर पर मरीजों को अब भी अप्रत्यक्ष रूप से अस्पताल की ही दवा दुकान से दवा लेने के लिए मजबूर किया जाता है।

अब निगाह प्रशासन की सख्ती पर

हालांकि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कहना है कि केवल बोर्ड लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जब तक पर्ची को पढ़ने योग्य बनाना अनिवार्य नहीं किया जाता, दवा–कमीशन व्यवस्था पर निगरानी नहीं होती, और उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, तब तक यह आदेश भी अन्य सरकारी निर्देशों की तरह कागजों तक सिमट कर रह सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि शासन इस आदेश का पालन सख्ती से कराता है या मरीज एक बार फिर सिस्टम के आगे मजबूर बने रहेंगे।

12 फरवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना की लाटरी का हुआ ऐलान

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा एक और लाटरी का ऐलान किया गया है। जिसके तहत अनेक नागरिको को स्वयं का आवास पाने का सौगात मिलेगा। इस योजना का उददेश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों और मध्यवर्गीय वर्ग के लोगों को सस्ती दरों पर घर उपलब्ध कराना है।

निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देशानुसार दिनांक 12 फरवरी को समय 12:30 बजे निगम मुख्य कार्यालय सभागार कक्ष में आवास आबंटन की लाटरी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की लाटरी पूरी पारदशिर्ता के साथ किया जाएगा। आवेदन करने के बाद पात्र हितग्राहियों को लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से चयनित किया जायेगा और आवास आबंटित किया जायेगा। सरकार का उददेश्य हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देना है। इस योजना से हर वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा।

ओवरब्रिज से रेलवे ट्रैक पर कूदे युवक की डायल-112 टीम ने बचाई जान

त्वरित और संवेदनशील रेस्क्यू से टली बड़ी अनहोनी, आरक्षकों को एसएसपी ने किया सम्मानित

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

मोहन नगरझधमधा नाका ओवरब्रिज क्षेत्र में एक युवक द्वारा मानसिक तनाव एवं नशे की स्थिति में ओवरब्रिज से नीचे रेलवे ट्रैक की ओर कूदने की सूचना मिलते ही डायल-112 मोहन नगर टीम ने तत्परता दिखाते हुए युवक की जान बचा ली। समय पर की गई रेस्क्यू कार्रवाई और तत्काल उपचार के कारण युवक सुरक्षित है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सूचना मिलते ही डायल-112 मोहन नगर की टीम बिना विलंब घटनास्थल पर पहुंची और अत्यंत सतकर्ता व मानवीय संवेदनशीलता के साथ रेलवे ट्रैक क्षेत्र में उतरकर युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके पश्चात उसे तत्काल शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां समय पर उपचार मिलने से उसकी जान बचाई जा सकी। रेस्क्यू किए गए युवक की पहचान भानुप्रताप देशमुख (उम्र 30

वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 13, जेवर सिरसा, दुर्ग के रूप में हुई है। वह नगर निगम भिलाई में सफाई कमर्चारी के पद पर कार्यरत है।

दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि मानसिक तनाव या किसी भी आपात स्थिति में घबराकर कोई गलत कदम न उठाएं। तत्काल सहायता के लिए 112 पर संपर्क करें। समय पर दी गई सूचना और सहयोग से किसी की भी अमूल्य जान बचाई जा सकती है।

आरक्षकों की सराहनीय भूमिका

इस साहसिक एवं मानवीय रेस्क्यू कार्रवाई में डायल-112 मोहन नगर में पदस्थ आरक्षक क्रमांक 1077 हिमांशु जंघेल एवं चालक क्रमांक 273 धर्मेद्र देशमुख की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही। उनकी त्वरित, सजग एवं कर्तव्यनिष्ठ कार्रवाई से एक अमूल्य जीवन बच सका। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दुर्ग द्वारा दोनों कमर्चारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

खास खबर

अहिवारा में रजत महोत्सव की धूम, उपभोक्ताओं और सेवाभावी कर्मचारियों को मिला सम्मान

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग-अहिवारा

अहिवारा संभाग एवं वितरण केंद्र अहिवारा के संयुक्त तत्वाधान में वार्ड क्रमांक 12 स्थित मंगल भवन में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 2026 का भव्य और सफल आयोजन किया गया। राज्य स्थापना के 25 गौरवशाली वर्षों को समर्पित इस उत्सव में न केवल विकास की गाथा दोहराई गई, बल्कि बिजली विभाग की रीढ़ कहे जाने वाले उपभोक्ताओं और कर्मठ कमर्चारियों का सम्मान कर रिश्तों की नई मिसाल पेश की गई।

समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्ष, जनपद पंचायत धमधा लीमन साहू और अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद अहिवारा विद्यानंद कुशवाहा उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में विधायक प्रतिनिधि अहिवारा सतीश साहू, अध्यक्ष, सरपंच संघ श्रीमती दामिनी साहू, पार्षद द्वय अनुज साहू एवं पुरुषोत्तम वर्मा एवं अध्यक्ष, सहकारी समिति अहिवारा पवन जैन ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम की शुरुआत में नगर पालिका परिषद के जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों और उपभोक्ताओं का पुष्पगुच्छ से गमजीशी भरा स्वागत किया गया। वक्ताओं ने छत्तीसगढ़ के 25 वर्षों के सफर में विद्युत विभाग के योगदान को रेखांकित किया और बेहतर भविष्य का संकल्प लिया।

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण उपभोक्ताओं का सम्मान रहा। विभाग ने पारदर्शिता और कर्तव्यपरायणता का परिचय देते हुए विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत घरेलू, गैर-घरेलू, कृषि, सोलर एवं बीपीएल श्रेणी के कुल 25 उपभोक्ताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही, विभाग के समर्पित सेवाभावी सेवानिवृत्त कमर्चारी लाइन इंस्पेक्टर नरेश सेन को उनकी दीघर्कालीन सेवाओं के लिए शाल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अधीक्षण अभियंता, दुर्ग वृत्त आर.के. मिश्रा, कायर्पालन अभियंता अहिवारा टी.एल. सहारे, सहायक अभियंता विजय बंजारे एवं कनिष्ठ अभियंता संदीप वर्मा ने अपनी उपस्थिति से आयोजन को गरिमा प्रदान की।

स्व-सहायता समूह व बैंक लिंकेज के माध्यम से हेमलता साहू ने सफल उद्यम की स्थापना की

दुर्ग। ग्राम ननकट्टी, जनपद पंचायत दुर्ग की हेमलता साहू ने यह साबित कर दिया है कि सही दिशा में किया गया छोटा सा प्रयास भी जीवन में बड़ी सफलता ला सकता है। हेमलता दीदी आराध्या स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई थी। हेमलता दीदी के पति चेतन लाल साहू निर्माण सामग्री और फेब्रिकेशन का छोटा व्यवसाय चला रहे थे, लेकिन पूंजी की कमी के कारण व्यवसाय को आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा था। इस परिस्थिति को समझते हुए हेमलता दीदी ने आराध्या स्व-सहायता समूह के माध्यम से पहला 60 हजार रूपए और फिर बैंक लिंकेज से एक लाख 43 हजार का ऋण लिया। इन राशि का उपयोग उन्होंने अंबुजा सीमेंट की डीलरशिप लेने में किया। इससे न केवल उन्हें अपने क्षेत्र में 15 किलोमीटर तक सीमेंट सप्लाई करने का काम मिलने लगा। उन्होंने समूह के माध्यम से और बैंक लिंकेज से दो लाख का ऋण लिया और सीमेंट, सरिया, गिट्टी, रेत और फेब्रिकेशन के लिए कच्ची सामग्री खरीदी। आज उनका वार्षिक टर्नओवर 50 लाख रूपए तक पहुँच चुका है, और लगभग 10 प्रतिशत लाभ मार्जिन के साथ वह प्रति वर्ष 5 लाख शुद्ध आय अर्जित कर रही हैं। हेमलता दीदी न केवल अपने पति के व्यवसाय की रीढ़ बनीं, बल्कि इसे एक सफल उद्यम में बदलकर अपने ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण सामग्री की आपूर्ति करने लगीं। आज वह ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत और जनपद के निर्माण कार्यो, विशेषकर प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्माण सामग्री की आपूर्ति कर रही है। साथ ही 4-5 लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया।

जिला शिक्षा अधिकारी ने किया जिले के विकासखण्ड दुर्ग-पाटन के विभिन्न शालाओं का औचक निरीक्षण

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

जिला शिक्षा अधिकारी अरविन्द मिश्रा द्वारा जिले के विकासखण्ड दुर्ग-पाटन के विभिन्न शालाओं का औचक निरीक्षण किया गया। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बालाजी नगर खुर्सीपार के निरीक्षण के दौरान छात्र-छात्राओं को मध्यान्ह भोजन गंदे स्थान पर परोसा जा रहा था तथा परिसर में गंदगी के बीच छात्र-छात्राएं भोजन करते पाये गये कोई भी शिक्षक देखभाल के लिए नहीं थे जिसके लिए प्रधानपाठक मीनूलाल को नोटिस जारी किया गया है।

शास.उ.मा.वि. सेक्टर-11 जोन-02 खुर्सीपार के निरीक्षण दौरान संस्था के निम्न उल्लेखित कमर्चारीगण 10.00 बजे तक विद्यालय नहीं पहुंचे थे। हेमन्त कुमार बघेल व्याख्याता एल.बी., श्रीमती नाजनी व्या.एल.बी., रिकी शर्मा व्या.एल.बी., हरिशचन्द्र वर्मा व्या.एल.बी., डां. श्रीमती दिप्ति सिंह गहरवार व्या.एल.बी., सुश्री अनिता बर्वे व्या., श्रीमती किरण एक्का व्या., श्रीमती पदमा साहू व्या. से.नि., संतगाम यादव व्या.एल.बी., चंचल ठाकुर सहा. शिक्षक विज्ञान, एम.एल. देवांगन स.शि. विज्ञान, श्रीमती टी.नेहा नायडू, सहा.ग्रे.2, मिलाप सिंह राजपूत सहायक ग्रेड-03, विजेन्द्र चौहान स.ग्रे. 3, उमेश कुमार दिल्लीवार शिक्षक पावर ट्रेड शाला निर्धारित समय तक उपस्थित नहीं हुए थे। जिस पर समस्त कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया हैं।

पूर्व माध्यमिक शाला भिलाई-03, मे मध्यान्ह भोजन प्रारंभ था जिस पर मिनू अनुसार छात्र-छात्राओं को मध्यान्ह भोजन का लाभ तथा साफ सफाई पर ध्यान देने के निर्देश दिये गये। प्राथमिक शाला जरवाय में निरीक्षण के दौरान मध्यान्ह भोजन निर्धारित मीनू अनुसार प्रदाय करने, बारहखड़ी, पहाड़ा पुस्तक वाचन के नियमित अभ्यास कराने, विद्याथिर्यो की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने तथा नियत समय पर अनिवार्य उपस्थिति के निर्देश दिये। शास.उ.मा.वि. जरवाय, के निरीक्षण दौरान हाई/ हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के प्राचार्यो को नियमित प्रायोगिक कार्य करने, ब्लू प्रिंट के अनुरूप 05 वर्षो के प्रश्न पत्रों को हल कराने, तिमाही, छमाही परीक्षा के आधार पर चिन्हांकित विद्याथिर्यो को सीमित पाठ्यक्रम में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कराने एवं प्रायोगिक परीक्षा के बाद भी बोर्ड परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व तक विद्याथिर्यो की नियमित उपस्थिति के निर्देश भी दिये।

सेजेस पुरैना का आकस्मिक निरीक्षण दौरान कमजोर बच्चों को चिन्हांकित कर विशेष कार्य योजना एवं 05 वर्ष के प्रश्न बैंक का नियमित अध्यापन कार्य कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। शासकीय हाईस्कूल सोमनी के निरीक्षण दौरान पूनम बघेल पाठकांन में हस्ताक्षर करके विद्यालय से अनुपस्थित पाई गई। जिस पर नोटिस जारी किया गया है। प्राथमिक / माध्यमिक शाला सोमनी के निरीक्षण दौरान कक्षा 08वीं के बच्चों में कक्षा अनुरूप योग्यता का अभाव, हिन्दी/अंग्रेजी में धारा प्रवाह वाचन का अभाव के साथ 08वीं तक के बच्चों को पहाड़ा का ज्ञान नहीं होना पाये जाने पर संबंधित पू.मा.शाला के प्रधानपाठक को नोटिस जारी किया गया है। प्राथमिक / माध्यमिक शाला सिरसाकला के निरीक्षण दौरान पाया गया कि विद्यालय में 11 कमरे मौजूद होने के बावजूद विद्यालय दो शिफट में संचालित किया जा रहा हैं जबकि 03 कमरे बंद पाये गये, अवलोकन उपरांत तीनो कमरों में शाला संचालन योग्य पाया गया है। उक्त संबंध में संबंधित प्राथमिक/ माध्यमिक के संस्था प्रमुख एवं सी.ए.सी. सिरसाकला को नोटिस जारी किया गया हैं। इसी संस्था से अनिता सिंह एवं अनिता चौधरी शाला समय बाद देर से शाला पहुंचने पर दोनों को नोटिस जारी किया गया है।

निरीक्षण के दौरान सभी प्राथमिक/ पूर्व माध्यमिक/हायर सेकेण्डरी के संस्था प्रमुखों को मध्यान्ह भोजन निर्धारित मीनू अनुसार प्रदाय करने, बारहखड़ी, पहाड़ा पुस्तक वाचन के नियमित अभ्यास कराने, विद्याथिर्यो की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने तथा नियत समय पर अनिवार्य उपस्थिति के निर्देश दिये। इसी प्रकार हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के प्राचार्यो को नियमित प्रायोगिक कार्य करने, ब्लू प्रिंट के अनुरूप 05 वर्षो के प्रश्न पत्रों को हल कराने, तिमाही, छमाही परीक्षा के आधार पर चिन्हांकित विद्यार्थीयों को सिमित पाठ्यकम में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कराने एवं प्रायोगिक परीक्षा के बाद भी बोर्ड परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व तक विद्याथिर्यो की नियमित उपस्थिति के निर्देश दिये गये।

पाटन अंचल में सामाजिक समरसता और जनसंपर्क का दिया सशक्त संदेश-कीर्ति

नई दृष्टिबिंदु / पाटन

जनपद पंचायत पाटन की अध्यक्ष श्रीमती कीर्ति नायक ने कल पाटन अंचल के विभिन्न ग्रामों में आयोजित सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता करते हुए जनसंपर्क किया और समाज को सकारात्मक दिशा देने का संदेश दिया।

अपने दौरे की शुरुआत उन्होंने ग्राम बेलौदी से की, जहाँ आयोजित गीता जयंती समारोह एवं कोसरिया यादव समाज के युवक-युवती परिचय सम्मेलन में वे मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गीता का संदेश कर्म, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने समाज को संगठित होकर शिक्षा, संस्कार और विकास के पथ पर आगे बढ़ने का आह्वान किया। इसके पश्चात श्रीमती नायक छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी समाज, दुर्ग राज के ग्राम मोरिंद में आयोजित अधिवेशन में सम्मिलित हुईं। यहाँ उन्होंने समाजजनों से आत्मीय भेंट कर उनकी कुशलक्षेम जानी तथा समाज की एकता, आपसी सहयोग और संगठनात्मक मजबूती पर विशेष बल दिया।

भारतीय जनता पार्टी जिला दुर्ग के निर्देशन में प्रभारी के रूप में उन्होंने दरबार मोखली मंडल अंतर्गत ग्राम फेकारी में कार्यकर्ता साथियों के साथ केंद्रीय बजट सत्र का सामूहिक श्रवण किया। इस अवसर पर उन्होंने बजट को जनकल्याणकारी बताते हुए कहा कि यह बजट ग्रामीण विकास, महिलाओं, युवाओं और किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

इसी क्रम में श्रीमती कीर्ति नायक भिलाई-3 चरोदा परीक्षेत्रीय स्तरीय महाराज श्री गुहा निषाद राज जयंती, नव-निर्मित सामाजिक सामुदायिक भवन के लोकार्पण एवं मड़ई-मिलन कार्यक्रम (ग्राम बटंग) में भी शामिल हुईं। उन्होंने महाराज श्री गुहा निषाद राज जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका जीवन साहस, त्याग और सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जिससे आज की पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए।

इसके साथ ही वे ग्राम बटंग में आयोजित कोसरिया पटेल समाज के नवनिर्मित समाज भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहीं और समाजजनों को बधाई देते हुए इसे सामाजिक गतिविधियों का सशक्त केंद्र बताया। सभी कार्यक्रमों में अध्यक्ष श्रीमती कीर्ति नायक ने अपने सारगर्भित एवं प्रेरक उद्बोधनों के माध्यम से सामाजिक एकता, सांस्कृतिक मूल्यों और विकास की भावना को सुदृढ़ किया।

नागरिक सहकारी बैंक के डायरेक्टर पद के चुनाव के लिए दाखिल किए नामांकन

चुनाव

बैंक के इतिहास में डायरेक्टर पद के लिए पहली बार बन रही है मतदान की स्थिति

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित दुर्ग के 12 संचालक मंडल सदस्य पद (डायरेक्टर) के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरु हो गई है। मंगलवार को प्रत्याशियों ने उत्साह के साथ नामांकन दाखिल किया। कुल 44 नामांकन प्राप्त हुए है। इनमें कुछ प्रत्याशियों के एक से अधिक नामांकन मिले है। यह नामांकन प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारी देवाशीष दास के देखरेख में पूरी की गई।

नामांकन प्रक्रिया के चलते बैंक मुख्यालय अस्पताल वार्ड पचरीपारा में प्रत्याशी, उनके समर्थक और बैंक से जुड़े सदस्य जुटे थे। जिससे नामांकन प्रक्रिया के दौरान गहमागहमी का माहौल निर्मित रहा। नागरिक सहकारी बैंक के इतिहास में संचालक मंडल सदस्य पद के लिए पहली बार मतदान की स्थिति बनते नजर आ रही है। लिहाजा प्रत्याशियों द्वारा दो अलग-अलग पैनलों में अपना नामांकन दाखिल किया गया है।

रुंगटा पैनल से प्रत्याशी कमलनारायण रुंगटा, मनोज ताम्रकार, तेजबहादुर बंछोर, संजय सिंह, अखिलेश मिश्रा, ज्ञानेश्वर ताम्रकार, पवन बड़जात्या, श्रीमती नीलू देवांगन, श्रीमती सुनीता अग्रवाल, अरविंद सुराना, श्रीपाल कोठारी, श्रीमती वसुन्धरा चौरे ने नामांकन दाखिल किया है, वहीं परिवर्तन पैनल से प्रत्याशी राजेश यादव, वेंकट साई शास्त्री राव, मंगल प्रकाश गुप्ता, दीपक चावड़ा, दिनेश मारोटी, रविशंकर भट्ट, अंबर ताम्रकार, अंजय ताम्रकार, पदम ताम्रकार, श्रीमती संध्या तिवारी, रजनी जोशी, श्रीमती वसुन्धरा चौरे द्वारा अपने नामांकन जमा किए गए है।

अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित संचालक मंडल सदस्य के एक पद के लिए केवल श्रीमती वसुन्धरा चौरे द्वारा ही नामांकन दाखिल किया गया है। जिनका निविरीध निर्वाचित होना तय है। जिसके चलते दोनो पैनल द्वारा श्रीमती वसुन्धरा चौरे को अपने पैनल से प्रत्याशी होने का दावा किया जा रहा है। इस चुनाव में 12 संचालक मंडल सदस्य पद में 10 पद सामान्य वर्ग (अनारक्षित) के लिए है। इनमें 2 पद महिला वर्ग और 2 पद सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउंटेंट) के लिए आरक्षित किए गए है।

इसके अलावा 1-1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित किए गए है। संचालक मंडल सदस्य पद के प्रत्याशियों द्वारा मंगलवार को दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच नामांकन पत्र जमा किए गए। 4 फरवरी को शाम 4 बजे से प्राप्त नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। जिसके उपरांत वैध नामांकन पत्रों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। नामांकन पत्रों की वापसी के लिए 5 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई। अभ्यर्थी सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। नामांकन वापसी की प्रक्रिया समाप्ति उपरांत अभ्यर्थियों की अंतिम सूची और उन्हें चुनाव चिन्ह का आबंटन किया जाएगा।

मतदान की स्थिति निर्मित होने पर 14 फरवरी को श्री गुर्जर क्षत्रिय गुजराती समाज भवन मोतीपारा में मतदान की प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी और इसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। मतदान के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे का समय निर्धारित किया गया है।

रिटर्निंग अधिकारी देवाशीष दास ने बताया कि संचालक मंडल सदस्यों के अलावा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सोसायटियों के प्रतिनिधियों व अन्य पदाधिकारियों के निर्वाचन की सूचना 16 फरवरी को जारी किया जाएगा। इन पदों पर निर्वाचन की प्रक्रिया 20 फरवरी को शाम 4 बजे से बैंक मुख्यालय अस्पताल वार्ड पचरीपारा में पूरी की जाएगी।

"कानून की बारीकियों के साथ रचनात्मकता का संगम": अग्रिम विवेचना, जमानत और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर हुई कार्यशाला

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय दुर्ग के नवीन सभागार में विधिक ज्ञान और कलात्मकता का एक अनूठा संगम देखने को मिला। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के तत्वावधान में "अग्रिम विवेचना, जमानत एवं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस" जैसे गंभीर, प्रासंगिक और समसामयिक विषयों पर एक विशेष कायर्शाला का आयोजन किया गया।

इस कायर्शाला का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के करकमलों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों ने कानून के तकनीकी पहलुओं को बहुत ही सरल अंदाज में प्रस्तुत किया। श्रीमती पल्लवी गुप्ता (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दुर्ग) ने 'अग्रिम विवेचना' (Further Investigation) की बारीकियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि एक बेहतर विवेचना ही न्याय की नींव होती है। श्रीमती शिक्षा मेश्राम (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दुर्ग) ने 'जमानत' (Bail) के नवीनतम प्रावधानों और प्रक्रियाओं पर विस्तृत जानकारी दी। सौरभ शेन्द्रे (असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल

सिस्टम दुर्ग) ने वतर्मान डिजिटल युग में 'इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस' की महत्ता, संग्रहण और न्यायालय में उनकी ग्राह्यता पर सारगर्भित वक्तव्य दिया।

इस अवसर पर अपने सारगर्भित उद्बोधन में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग ने संबोधित किया कि "बदलते दौर में अपराधों की प्रकृति हाईटेक हो गई है, ऐसे में "अग्रिम विवेचना, जमानत एवं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस" की बारीकियों को समझना अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों के लिए अनिवार्य है।" उन्होंने आपराधिक न्याय प्रणाली में अग्रिम विवेचना, जमानत के सिद्धांत तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डालते हुए इनके विधिसम्मत एवं संवेदनशील प्रयोग की आवश्यकता पर विशेष बल दिया।

कार्यक्रम के अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि अग्रिम विवेचना, जमानत एवं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वतर्मान आपराधिक न्याय प्रणाली के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं। उन्होंने विवेचना को निष्पक्ष, वैज्ञानिक एवं विधिसम्मत ढंग से किए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इससे अपराध के सही अनावरण के साथ-साथ निदीष व्यक्तियों के अधिकारों की भी रक्षा होती है। जमानत के संदर्भ में उन्होंने 'बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन' के सिद्धांत का उल्लेख किया तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के विधि के अनुरूप संग्रहण एवं प्रस्तुतीकरण को समय की आवश्यकता बताया।

रंगोली और पेंटिंग प्रदर्शनी बनी आकर्षण का केंद्र

कायर्शाला की गंभीरता के बीच रचनात्मकता के रंगों ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा विषय वस्तु पर आधारित एक भव्य और संदेशपरक रंगोली तथा बैनर तैयार किया गया था, जिसकी सभी ने सराहना की। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण वह 'चित्रकला प्रदशर्नी' (Painting Exhibition) रही, जिसमें केन्द्रीय जेल दुर्ग के बंदियों और लीगल एड डिफेंस काउंसिल (LADC) के स्टॉफ द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया गया। इन पेंटिंग्स के माध्यम से न केवल कला का प्रदर्शन हुआ, बल्कि बंदियों और विधिक कार्यकर्ताओं की छिपी हुई प्रतिभा और भावनाओं को भी एक मंच मिला। इस अवसर पर जिला न्यायालय दुर्ग के न्यायाधीशगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के सचिव, जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग के अधिवक्तागण, अभियोजन अधिकारीगण और न्यायालयीन एवं विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के कमर्चारीगण उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ में ई-गवर्नेंस की नई गति : 'डिजिटल, दक्ष व विकासशील प्रशासन' की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

सामान्य प्रशासन विभाग ने iGOT प्रशिक्षण के माध्यम से 120 अधिकारियों का दस बैचों में क्षमता संवर्धन

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश में ई-गवर्नेंस व्यवस्था को सुदृढ़, प्रभावी एवं परिणामोन्मुखी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं दूरदर्शी पहल की गई है। इस क्रम में iGOT (Integrated Government Online Training) प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुल 120 अधिकारियों को दस बैचों में विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ को डिजिटल ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना तथा तेज, पारदर्शी एवं उत्तरदायी निर्णय प्रक्रिया के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास को गति प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ शासन की यह पहल 'डिजिटल, दक्ष एवं विकासशील प्रशासन' के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगी।

उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चंपावत के नेतृत्व में विगत दिनों iGOT प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 1200 अधिकारियों एवं कमर्चारियों को प्रशिक्षित कर एक उल्लेखनीय प्रशासनिक कीतिर्मान स्थापित किया गया है। यह पहल अधिकारियों एवं कमर्चारियों में नेतृत्व क्षमता, प्रस्तुतिकरण कौशल तथा ज्ञान-वितरण को सुदृढ़ करने के साथ-साथ उनके बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा एवं नवाचार की संस्कृति को भी प्रोत्साहित कर रही है। प्रशासनिक दक्षता को और अधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों एवं कमर्चारियों को उचित प्रोत्साहन एवं पुरस्कार प्रदान किया जाना आवश्यक है, जिससे वे भविष्य में और अधिक प्रतिबद्धता, दक्षता एवं नवाचार के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

सामान्य प्रशासन विभाग की अवर सचिव अंजू सिंह ने आज मंत्रालय में प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को iGOT प्लेटफॉर्म पर पंजीयन (रजिस्ट्रेशन), लॉग-इन प्रक्रिया, प्रशिक्षण मॉड्यूल पूर्ण करने, प्रमाण पत्र प्राप्त करने, प्रमाण पत्र डाउनलोड करने तथा उसे व्यक्तिगत उपलब्धियों (Achievement) में अपलोड करने की संपूर्ण प्रक्रिया का विस्तृत एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान के अंतर्गत आयोजित किया गया, जो विभिन्न विभागों के अधिकारियों को उनके प्रशासनिक दायित्वों, कार्यप्रणाली तथा योजनाओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक चरण है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन सामान्य प्रशासन विभाग की अवर सचिव अंजू सिंह के मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि डिजिटल प्रशासन केवल तकनीकी परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक कायर्संस्कृति में मूलभूत बदलाव का सशक्त माध्यम है। उन्होंने बताया कि iGOT के माध्यम से प्राप्त प्रशिक्षण मंत्रालयीन अधिकारियों को ई-ऑफिस एवं ई-कैपेसिटी बिल्डिंग प्रणाली के प्रभावी, पारदर्शी तथा समयबद्ध क्रियान्वयन में सक्षम बनाएगा।

ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी संचालन को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को विशेष रूप से डिजिटल फाइल मूवमेंट, प्रक्रिया सरलीकरण, नीतियों एवं योजनाओं के समयबद्ध निष्पादन तथा जनसेवा की गुणवत्ता एवं प्रशासनिक दक्षता में सुधार से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रशासनिक आधुनिकीकरण की दिशा में संचालित सतत सुधार प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रशिक्षण में सहभागिता करने वाले अधिकारियों ने कार्यक्रम को अत्यंत उपयोगी एवं व्यवहारिक बताते हुए कहा कि इससे नीतिगत निणर्यों एवं योजनाओं के प्रभावी एवं धरातल पर क्रियान्वयन में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित होगा।

खास खबर

यात्रियों की सुविधा में नया आयाम : पर्यटन मंत्री अग्रवाल के प्रयास से अंबिकापुर-दुर्ग एक्सप्रेस अब रायपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म-1 से चलेगी

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने यात्रियों की सुविधा संवर्धन की दिशा में एक सराहनीय पहल की है। उनके प्रयासों के फलस्वरूप गाड़ी संख्या 18242 (अंबिकापुर-दुर्ग एक्सप्रेस) अब रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 01 से प्रस्थान करेगी। यह व्यवस्था दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे प्रशासन के सहयोग से लागू कर दी गई है।

राजधानी रायपुर की आम जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल के कार्यालय ने मंडल रेल प्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर को पत्र लिखकर इस सुविधा की मांग की थी। पत्र में यात्रियों को होने वाली असुविधाओं का विस्तृत उल्लेख करते हुए त्वरित कार्रवाई की अपील की गई थी। मंडल रेल प्रबंधक द्वारा इस पत्र का शीघ्र संज्ञान लेते हुए गाड़ी को प्लेटफॉर्म-01 पर लेने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस जनहितैषी निर्णय से अंबिकापुर, दुर्ग सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से आने वाले हजारों यात्रियों को अब प्लेटफॉर्म बदलने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। विशेष रूप से बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों के लिए यह व्यवस्था वरदान साबित होगी। मंडल रेल प्रबंधक एवं संबंधित रेल अधिकारियों के सहयोग के लिए पर्यटन मंत्री अग्रवाल ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी है।

कोनी मोपका बायपास फोरलेन निर्माण कार्य के लिए राशि स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के रजत जयंती महोत्सव के विशेष अवसर पर राज्य के विभिन्न जिलों में जन सामान्य का आवागमन सुगम बनाने के लिए महत्वपूर्ण सड़क निर्माण के कार्यों को कराने के लिए स्वीकृति जारी की गई है। इसी कड़ी में रजत जयंती के विशेष मौके पर जिला बिलासपुर के अंतर्गत कोनी मोपका बायपास मार्ग लम्बाई 13.40 किलोमीटर फोरलेन निर्माण कार्य के लिए 20 करोड़ 51 लाख 80 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है।

नालियों व मार्गों में चला सफाई अभियान

रायपुर। रायपुर नगर पालिक निगम जोन 5 स्वास्थ्य विभाग को स्वच्छता से सम्बंधित प्राप्त जनशिकायत को तत्काल संज्ञान में लेते हुए नगर निगम आयुक्त विश्वदीप द्वारा दिए गए आदेशानुसार और नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणीग्रही और जोन 5 जोन कमिश्नर खीरसागर नायक के निर्देशानुसार नगर निगम जोन 5 स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जोन स्वास्थ्य अधिकारी संदीप वर्मा के मार्गनिर्देशन में जोन 5 क्षेत्र अंतर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नगर वार्ड क्षेत्र में डीडी नगर सेक्टर - 1 क्षेत्र में नालियों और मागी की सफाई करवाकर कचरा एकत्रित करवाकर जनहित में जनस्वास्थ्य सुरक्षा बाबत स्वच्छता कायम की और प्राप्त जनशिकायत का त्वरित निदान किया।

मुख्य सचिव ने रेल परियोजनाओं सहित अहम मुद्दों पर हुई विस्तार से चर्चा

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में यहां मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ में स्थित रेल परियोजनाओं संबंधी समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य की प्रमुख रेल परियोजनाओं के कार्यो की गति, नई रेल्वे लाईनों के कार्यो की स्थिति, सहित परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और फारेस्ट क्लीयरेंस, सर्वे, मुआवजा अवार्ड, जमीन के बदले जमीन, नामांतरण जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से कहा कि जहां पर रेल परियोजनाएं हैं वहां अपने स्तर पर रेल्वे परियोजनाओं के लिए जरूरी कार्यवाही शीघ्रता से पूर्ण करें, जिससे रेल्वे अपनी के काम की शुरूआत कर सकें। इसी तरह से सीएसईबी द्वारा विद्युत उपयोगिताओं के स्थानांतरण हेतु संयुक्त सर्वे एवं स्टीमेट के कार्यों में तेजी लाने कहा गया है।

बैठक में जिला मनेन्द्रगढ़ एवं सूरजपुर के अंतर्गत बोरीढांड रेल्वे लाईन दोहरीकरण, बिलासपुर-दाधापारा-बिल्हा-दागोरी चौथी लाईन परियोजना, कोरबा-बलौदा-राजनांदगांव परियोजना, निपनिया-भाटापारा चौथी लाईन सहित रावघाट-जगदलपुर नई सिंगल लाईन सहित राज्य की अन्य रेल परियोजनाओं के कार्यो की विस्तार से चर्चा की गई।

सामान्य प्रशासन विभाग एवं रेल परियोजनाओं के सचिव श्री रजत कुमार, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव सहित रेल्वे, वन विभाग, राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, कोण्डागांव, नारायणपुर, कांकेर जिले के कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम शामिल हुए।

सूझ-बूझ से कंपनी को करोड़ों रूपए की बचत, 12 कर्मी सम्मानित

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी के 12 कमिर्यो को उनके उत्कृष्ट कार्यो के लिए प्रबंध निदेशक जनरेशन एस के कटियार के हाथों सम्मानित किया गया। इन कमिर्यो के योगदान से कंपनी प्रबंधन को कई करोड़ रूपए की बचत हुई जिससें कंपनी को आर्थिक लाभ के साथ संभावित हानियों से भी बचाया गया। श्री कटियार ने कमिर्यो को बधाई देते हुए कहा कि पुरस्कृत कर्मी को सम्मान देना प्रबंधन का दायित्व है ,ताकि उनके कार्यो का लाभ एवं अनुभव अन्य कर्मी भी ले सकें और कार्यालय में एक सकारात्मक वातावरण निर्मित किया जा सके।

सम्मानित एवं पुरस्कृत कमिर्यो में शामिल हैं - पराग हरिनखेरे सहायक अभियंता द्वारा गारे पेलमा सेक्टर-तीन कोयला खदान के माईन डेव्हलपर कम आपरेटर गारे पेलमा-।।। कोलियरीज लिमि. के साथ आर्बिट्रेशन में कोर्ट द्वारा आर्बिट्रेशन के निर्णय को रदद् कर कम्पनी के पक्ष में निर्णय दिया गया जिससे रू. 195.00 करोड़ की संभावित हानि से कंपनी को बचाया गया। अनिल कुमार शर्मा, अधीक्षण अभियंता (सिविल) द्वारा कोरबा पश्चिम एवं कोरबा पूर्व स्थित संयंत्रो एवं कॉलोनी परिसर में सिविल मेंटनेंस कार्य संपादित किया गया,जिससे कंपनी को लगभग रूपये दो करोड़ प्रतिवर्ष का आय संभावित है। श्री दीपक कोठारी, अधीक्षण अभियंता को 660-660 परियोजना की स्थापना हेतु पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने हेतु आवश्यक पर्यावरण मूल्यांकन प्रतिवेदन ,डाटा का संकलन, वन्य जीवन अध्ययन, जनसुनवाई तथा आवश्यक पालन प्रतिवेदन कार्य दक्षता से पूर्ण किया गया।

आशीष सिंह चंदेल, सहायक अभियंता, द्वारा 2000 मेगावॉट सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु संयुक्त उपक्रम कंपनी छत्तीसगढ़ ग्रीन एनर्जी लि. के गठन एवं 06 मेगावॉट फ्लोटिंग सोलर संयंत्र स्थापना हेतु निविदा प्रक्रिया का निष्पादन किया गया। हेमन्त कुमार साहू, कायर्पालन अभियंता द्वारा हसदेव ताप विद्युत गृह, कोरबा (पश्चिम) के कार्य प्रकरणों की 47 निविदाओं का कार्य सम्पादित कर करीब 5.5 करोड़ रूपए बचाने का उल्लेखनीय कार्य किया गया। जयराम केंवट, कार्या. सहा. श्रेणी - दो,द्वारा देयकों का समयबद्ध निपटान करने से कंपनी को कोई देनदारी एवं आयकर संबंधी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ।

नीरज साहू, प्रबंधक (वित्त/के.ले.ई.),द्वारा वेतन, पेंशन, देयकों पर वैधानिक कटौती जैसे आयकर/टीडीएस/जी.एस.टी.टी.डी.एस की कटौती का समय पर भुगतान करने से किसी भी प्रकार का वित्तीय भार नही आया। श्रीमती नीतू मुखर्जी, उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) द्वारा ए.जी. आडिट में विशेष प्रयास के फलस्वरूप लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन को निरस्त कराने एवं आंतरिक आडिट में तेजी एवं वार्षिक बजट को समय पूर्व कराये जाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। श्रीमती अमिता बारा, कायर्पालन अभियंता द्वारा आईटी उन्यन के कार्य जैसे आईएसओ/आईइसी 27001 प्रमाणन, सीएसपीजीसीएल हेतु आपरेशन टेक्नोलॉजी ओटी सिस्टम हेतु वेएपीटी आडिट तथा ओटी नेटवर्क संरचना का सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया।

मनीष कुम्भकार, अधीक्षण अभियंता द्वारा गृह कोरबा (पश्चिम) इकाई क्र. 1 एवं 4 का वार्षिक रख-रखाव का कार्य निर्धारित समयावधि में सम्पन्न किया गया। देवांश सराफ,कायर्पालन अभियंता, द्वारा एईबीएएस (आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली) का क्रियान्वयन सक्रियता एवं तत्परता से किया गया। देवलाल साहू,अधीक्षण अभियंता द्वारा ई आफिस का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य के मतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद में संशोधित गाइडलाइन दरें लागू

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ में 20 नवंबर 2025 से लागू की गई नवीन गाइडलाइन दरों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार पुनरीक्षण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। राज्य शासन द्वारा पूर्व में जिला मूल्यांकन समितियों को यह निर्देश जारी किए गए थे कि यदि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप गाइडलाइन दरों में संशोधन की आवश्यकता हो, तो उसके प्रस्ताव केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जा सकते हैं।

शासन के इन निर्देशों के अनुपालन में धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से संशोधन संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें तीनों जिलों से प्राप्त प्रस्तावित गाइडलाइन दरों का गहन परीक्षण किया गया। बैठक में समग्र रूप से विचार-विमर्श के बाद धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा भेजे गए गाइडलाइन दर संशोधन प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित संशोधित गाइडलाइन दरें धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों में 4 फरवरी 2026 से प्रभावशील होंगी। आम नागरिकों, संपत्ति क्रेता-विक्रेता तथा अन्य संबंधित हितधारकों को इन नवीन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों एवं विभाग की आधिकारिक वेबसाइट में उपलब्ध है। राज्य शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अन्य जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त होने वाले संशोधित गाइडलाइन दरों के प्रस्तावों पर भी शीघ्र कार्रवाई करते हुए उन्हें क्रमशः जारी किया जाएगा। यह प्रक्रिया प्रदेश में संपत्ति मूल्यांकन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, युक्तिसंगत और जनोपयोगी बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

सरकार का श्रमिकों को तोहफा - बटन दबाकर 9328 श्रमिकों के खाते में राशि की अंतरित

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन के श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन और छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कमर्कार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह ने बटन दबाकर डीबीटी के माध्यम से प्रदेश के 9328 निर्माण श्रमिकों के खाते में 18.23 करोड़ की राशि अंतरित कर विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया। आज मंगलवार को नवा रायपुर अटल नगर, स्थित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कमर्कार कल्याण मंडल की बोर्ड की बैठक श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन और बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह की विशेष उपस्थिति में हुई।

इस अवसर पर श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय दोनों के मंशा अनुरूप प्रदेश के श्रमिक भाई बहनों के साथ साथ उनके परिवार जनों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा उपकरण, खेल प्रोत्साहन, सशक्तिकरण, आवास, पेंशन समेत सभी योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वन कर समय सीमा में योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। साय सरकार श्रमिक हितैषी सरकार है। मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश पर विगत दो वर्षो में अब तक श्रम विभाग के अधीन सभी मंडलों से 800 करोड़ से अधिक की राशि श्रमिक भाई बहनों के खाते में अंतरित की जा चुकी है। सिर्फ छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कमर्कार कल्याण मंडल से ही अब तक 11 लाख से अधिक श्रमिकों को 500 करोड़ से अधिक की राशि से लाभान्वित किया गया।

इस अवसर पर मंडल के अध्यक्ष रामप्रताप सिंह ने इस अवसर पर कहा की छत्तीसगढ़ सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में श्रमिकों को योजनाओं का लाभ सरल और पारदर्शी तरीके से सीधे उनके हाथों तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है।

मिनीमाता महतारी जतन योजना श्रमिक 3555 राशि 71100000, मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना श्रमिक 1098 राशि 4067595, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना श्रमिक 278 राशि 6248582, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना श्रमिक 6 राशि 120000, मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना श्रमिक 747 राशि 1120500, निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रात्साहन योजना श्रमिक 1 राशि 50000, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना श्रमिक 318 राशि 32200000, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना श्रमिक 2673 राशि 53460000, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना श्रमिक 537 राशि 10740000, मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना श्रमिक 23 राशि 2300000, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना श्रमिक 84 राशि 126000, दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना श्रमिक 8 राशि 800000 शामिल है।

आंदोलन | दीपक बैज के नेतृत्व में कवर्धा में फूटा जन आक्रोश, भाजपा सरकार कटघरे में

भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में आज कबीरधाम जिले के कवर्धा में कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक कलेक्ट्रेट घेराव कर भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, किसान, मजदूर, महिलाएं और युवा सड़कों पर उतरे और भाजपा सरकार के खिलाफ उग्र जनआंदोलन खड़ा किया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही गरीब, किसान और मजदूरों के हक पर सीधा हमला किया है। कांग्रेस जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूरन सड़कों पर उतरी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की 11 हजार से अधिक पंचायतों में मनरेगा का काम ठप पड़ा है। भाजपा सरकार मजदूरों से उनका संवैधानिक अधिकार छीन रही है। यूपीए सरकार के समय डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा लागू मनरेगा ने पंचायतों को मजबूत किया था, लेकिन भाजपा ने पंचायत व्यवस्था को पंगु बना दिया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बैज ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकारै ंत्र् के नाम पर विशेष रूप सेै ज्ञ्ै ब और कमजोर वर्गों को निशाना बनाकर उनके वोट काटने की साजिश कर रही है। यह लोकतंत्र की सीधी हत्या है और गरीबों को मतदान से दूर रखने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि कवर्धा गृह मंत्री विजय शर्मा का गृह जिला होने के बावजूद यहां हत्या, लूट, चोरी, डकैती, बलात्कार और अपहरण की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अपराधी बेखौफ हैं और प्रशासन भाजपा के इशारे पर सच्चाई दबाने में लगा है। लोहारीडीह, लालपुर और पुलिस कस्टडी में हुई मौतों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में कांग्रेस के दबाव में कार्रवाई हुई, लेकिन पीड़ित परिवारों को आज तक पूरा न्याय नहीं मिला।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों से धान खरीदना ही नहीं चाहती। प्रदेश में 3 लाख से अधिक किसान आज भी धान बेचने से वंचित हैं। किसान दफ्तर-दफ्तर भटक रहे हैं और सरकार आंख मूंदकर बैठी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में हजारों करोड़ रुपये का धान घोटाला हुआ है और कवर्धा में 7 करोड़ रुपये का धान घोटाला उजागर होने के बावजूद कार्रवाई केवल छोटे लोगों पर की जा रही है।

धरना प्रदर्शन व घेराव कार्यक्रम में पूर्व विधायक ममता चंद्राकर, भुनेश्वर बघेल, जिला अध्यक्ष नवीन जायसवाल, थानेश्वर पाटिल, पदम कोठारी, अर्जुन तिवारी, लालजी चंद्रवंशी, महेश चंद्रवंशी, कलीम खान, वीरेंद्र जांगड़े, जगमोहन साहू, राधेलाल भास्कर, सीमा अनंत अगम, रवि चन्द्रांवशी, पदुम सेन, अशोक सिंह ठाकुर, छबि वर्मा, मणिकांत त्रिपाठी, चेतन वर्मा, घनश्याम साहू, उतरा दिवाकर, प्रभाती मरकाम, शौखी साहू, चंद्रभान कोसले, कलीम खान, शीतेष चंद्रवंशी, गोपाल चंद्रवंशी, तुकाराम चंद्रवंशी, आनंद सिंह ठाकुर, मनीष शर्मा, गोपाल चंद्रवंशी, प्रशांत परिहार, वैभव ठाकुर, आकाश केसरवानी, मेहुल सत्यवंशी, राजेन्द्र मार्कण्डेय, आशु साहू, मुकुंद माध्व कश्यप, वाल्मीकि वर्मा, अश्वनी वर्मा, विक्की वर्मा, सुजल ठाकुर, आशीष गुप्ता, सुधांशु बघेल, अमन पाटस्कर, कन्नू आमदे, नरेंद्र वर्मा, अमन वर्मा, तुषार वर्मा, भुवनेश्वर पटेल, चोवा राम साहू, जुबी खान, नेमी चंद पटेल, भगवान सिंह पटेल, गब्बर खान, शेष बैस, रवि कांत ठाकुर, संतोष यादव, जलेश यादव, अजहर खान, महेंद्र कुंभकार, आनंद कुंभकार, भोलाराम चंद्रवंशी, रोहित चंद्रवंशी, विनोद चंद्रवंशी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे ।

'वूमेन फॉर वेटलैण्ड्स' अभियान पोस्टर का मुख्यमंत्री विष्णु देव साय किया अनावरण

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

विश्व आद्रर्भूमि दिवस के अवसर पर बीते दिनों मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री निवास में 'वुमेन फॉर वेटलैण्ड्स' अभियान के पोस्टर का अनावरण किया, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आद्रर्भूमि एवं प्राकृतिक जल-स्रोतों के संरक्षण हेतु चलाए जा रहे इस अभियान की सराहना की।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जल ही जीवन है और आद्रर्भूमियां मानव सभ्यता की अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मातृशक्ति को इस पवित्र अभियान से जोड़ना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रेरणादायी कदम है। मुख्यमंत्री साय ने यह भी कहा कि 'नदियां, तालाब, कुएं, पोखर और आद्रर्भूमियां केवल जल-स्रोत नहीं, बल्कि जीवनदायिनी प्रकृति की पहचान हैं। इन्हें बचाना हम सभी का सामूहिक दायित्व है।'

प्रज्ञा निर्वाणी चला रहीं व्यापक जन-जागरण अभियान

'वूमेन फॉर वैटलैंड्स' अभियान की संस्थापक एवं महिला मोर्चा की

जागरूकता अभियान

विश्व आद्रर्भूमि दिवस पर जल-स्रोत संरक्षण का दिया संदेश

जिला अध्यक्ष प्रज्ञा निर्वाणी द्वारा प्रदेशभर में आद्रर्भूमि संरक्षण हेतु निरंतर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है,इस अभियान के अंतर्गत तालाब, नहर, कुएं, नदियों एवं प्राकृतिक जल-स्रोतों के संरक्षण के लिए महिलाओं को संगठित किया जा रहा है।

प्रज्ञा निर्वाणी ने मुख्यमंत्री को नवागढ़ स्थित गिधवा-परसदा-नगधा पक्षी विहार क्षेत्र को रामसर साइट घोषित करने हेतु ज्ञापन भी सौंपा, सी एम साय ने कहा 'महिलाएं प्रकृति की प्रथम संरक्षक हैं,यदि मातृशक्ति आगे आएगी तो जल-स्रोतों का संरक्षण जन-आंदोलन बन जाएगा। पोस्टर अनावरण कार्यक्रम के दौरान प्रसन्ना अवस्थी, प्राची शर्मा, प्रणीता शर्मा,आरविका अवस्थी सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे।

संपादकीय

राजनीति की गुंजाइश तो हमेशा रहती है

किसी भी राज्य में कोई भी सरकार कोई भी ऐसा काम तो कर नहीं सकती कि उस पर विपक्षी दल राजनीति ही न कर सके। कहीं न कहीं कुछ छूट जाता है, कहीं न कहीं कोई कमी रह जाती है। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं चाहती है कि वह कोई काम पूरा न करे व कोशिश तो करती है कि तय समय के भीतर वह जो चाहती है, वह हो जाए लेकिन कई कारणों से ऐसा हो नहीं पाता है जिसे सरकार भले ही अपनी असफलता न माने लेकिन विपक्षी दल तो उसे सरकार की असफलता मानेगा भी और उस पर राजनीति करेगा भी कि सरकार ने जो कहा था वह कर नहीं पाई। विपक्ष तो दावा करेगा ही कि वह जैसा कह रहा था, वैसा ही हुआ है। सरकार ने कहा था कि वह किसानों का पूरा धान खरीदेगी, वहीं विपक्ष ने कहा था सरकार किसानों का पूरा धान खरीदना ही नहीं चाहती है।

राज्य मे साय सरकार ने किसानो का धान समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए पूरे राज्य पिछली बार से ज्यादा अच्छी तैयारी की थी क्योंकि हर बार सरकार की कोशिश यही रहती है कि ज्यादा किसानों का धान पिछली बार से ज्यादा खरीदा जाए। किसानों को धान बेचने में कोई परेशानी न हो, उनको टोकन में कोई परेशानी न हो, उनको धान का भुगतान होने में कोई दिक्कत न हो। फिर भी किसानों को धान बेचने में कोई न कोई परेशानी हो जाती है,बहुत सारे किसान समय पर धान बेच नहीं पाते हैं। इस बार भी यही हुआ है जितने किसानों ने पंजीयन कराया था, उनमें से खबरों के मुताबिक ढाई लाख किसान धान नहीं बेच पाए हैं।आंकड़ों के मुताबिक इस बार धान बेचने के लिए 27 लाख से ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया था जिसमें से 25 लाख किसान धान बेच चुके है तथा ढाई लाख किसान धान बेचने के लिए टोकन नहीं कटा पाए हैं।

सरकार किसानों का धान खरीदने के लिए सीमा तय कर देती है कि इस दिन से धान खरीदी शुरू होगी और इस दिन तक होगी। इस दौरान सभी किसानों को अपना धान बेचना होता है,सरकार पहले से धान खरीदी का लक्ष्य तय कर देती है।ऐसा इसलिए करती है ताकि ज्यादा किसानों का ज्यादा धान खरीदा जा सके।पिछले साल सरकार ने किसानों से 149 लाख टन धान खरीदा था इस बार तय दिन तक 139 लाख टन धान की खरीदी हो सकी है।टन में तो ऐसा लगता है कि सरकार ने पिछली बार से 10 लाख टन धान कम खरीदा है लेकिन जब प्रतिशत की बात आती है तो आंकड़ों से पता चलता है कि पिछली बार सरकार ने कुल पंजीयन कराने वाले किसानों में 91 प्रतिशत किसानों का धान खरीदा था जबकि इस बार जितने किसानों ने पंजीयन कराया है उसमे से 92 प्रतिशत किसानों का धान सरकार ने खरीदा है यानी सरकार कह सकती है कि उसने तो पिछली बार से ज्यादा किसानों से धान खरीदा है, यह सच है लेकिन विपक्ष को तो कहने का मौका मिलेगा कि सरकार ने सभी किसानों का धान नहीं खरीदा है।

यह सच है कि जितने किसानों ने पंजीयन कराया था, उसमें से ज्यादा से ज्यादा किसानों का धान सरकार ने खरीदने का प्रयास किया है लेकिन फिर भी आए दिन खबरें तो आती रही है कि किसानों को टोकने कटाने में परेशानी हो रही है, धान नहीं बेच पाने पर कुछ किसानों ने आत्महत्या का प्रयास भी किया है, किसानों ने कई बार चक्का जाम भी किया है। किसानों की परेशानी को देखते हुए कांग्रेस ने सरकार से धान खरीदी खत्म होने के पहले से मांग की थी बहुत सारे किसान अपना धान नहीं बेच पाए हैं, इसलिए सरकार को एक माह या पंद्रह दिन धान खरीदने का समय बढ़ाना चाहिए। धान खरीदी खत्म हो चुकी है, यह साफ भी हो गया है कि बहुत सारे किसान अपना धान नहीं बेच पाए हैं फिर भी सरकार की तरफ से अभी तक तो कहा नही गया है कि सरकार बचे किसानों का धान खरीदने के लिए समय बढ़ाएगी। माना जा रहा है कि सरकार ने जितना धान खरीद लिया है, वह उसे पर्याप्त मानती है और अब और धान नही खरीदना चाहती। पिछली बार ज्यादा धान खरीदने के कारण सरकार को बाद में धान कम दाम पर बेचना पड़ा था और सरकार को इससे घाटा हुआ था हो सकता है कि सरकार ने पिछली बार के घाटे को देखते हुए इस बार तय समय तक जितना धान खरीदा जा सका है उसे बहुत मानती है। इस बार वह ज्यादा धान खरीद कर धान खरीदी में घाटा नहीं उठाना चाहती है।

सरकार कितना भी धान खरीदे यदि कांग्रेस यह तो देखेगी नही कि सरकार कितना धान किसानों से खरीदा है वह तो यह देखेगी कि सरकार ने कहा था कि वह किसानों का पूरा धान खरीदेगी कितने किसानों का धान सरकार ने नहीं खरीदा है यानी कांग्रेस के लिए यह अहम बात है कि कितने किसान अपना धान नहीं बेच पाए हैं वह तो सरकार से पहले से मांग कर रही हैं कि बहुत सारे किसान धान नहीं बेच पाए इसलिए उनका धान खरीदने के लिए सरकार धान खरीदने का समय बढ़ाए। सरकार किसी भी कारण से समय नहीं बढ़ाती है तो कांग्रेस तो सरकार पर आरोप लगाएगी ही कि उसने वादा करके किसानों का पूरा धान नहीं खरीदा।छत्तीसगढ़ की राजनीति में किसानों का समर्थन व नाराजगी बहुत मायने रखती है।जिससे किसान खुश वह सरकार सफल मानी जाती है जिससे किसान नाराज वह सरकार असफल मानी जाती है।

ट्रंप का भविष्य ट्रंप

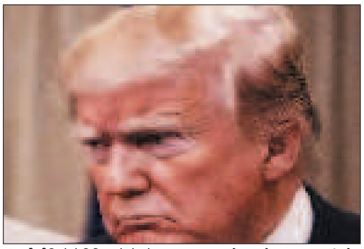

ट्रंप की नीतियों ने विभिन्न देशों को नए साथी और नए अवसर ढूंढने के लिए मजबूर किया है। जब अमेरिका ने अपने साथ सम्मानजनक ढंग से कारोबार के रास्ते बंद कर दिए हैं, तो लाजिमी है, देश नए विकल्प की तलाश करेंगे।

भारत और यूरोपियन यूनियन (ईयू) के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति बनने की खबर आते ही अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ईयू को आगाह कि वह अपने खिलाफ युद्ध के लिए धन मुहैया कराने जा रहा है। कहा कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद कर उसे व्यापारिक सहारा देता है। यूरोप रूस के हमले की आशंका से पीड़ित है, लेकिन अब वह भारत को लाभ पहुंचाने जा रहा है। इसके पहले कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने चीन से व्यापार समझौता किया, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप भड़क गए।

अपने चिर-परिचित अंदाज में कार्नी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कनाडा पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। मगर अब कार्नी ने मार्च में भारत आने का इरादा जता दिया है। इसी बीच ट्रंप दक्षिण कोरिया पर भी खफा हो गए हैं और उस पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने इस महीने के पहले हफ्ते में चीन की यात्रा की थी। उनके बाद स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्लेलिन भी चीन गए और अब अगले मंगलवार को ब्रिटिश प्रधानमंत्री कियर स्टार्मर बीजिंग पहुंच रहे हैं। इस यात्रा से ठीक पहले ब्रिटिश सरकार ने लंदन में चीन के प्रस्तावित भव्य दूतावास के निर्माण को हरी झंडी दे दी, जिसे कई साल से रोक रखा गया था।

उपरोक्त तमाम घटनाओं में एक समान तत्व की तलाश की जा सकती है। खुद ट्रंप प्रशासन की नीतियों ने विभिन्न देशों को नए साथी ढूंढने और नए अवसर तलाशने के लिए मजबूर किया है। जब अमेरिका ने अपने साथ सम्मानजनक ढंग से कारोबार के रास्ते बंद कर दिए हैं, तो लाजिमी है, विभिन्न देश नए विकल्प की तलाश करेंगे। लेकिन ऐसी हर घटना से ट्रंप की महत्त्वाकांक्षा पर आघात पहुंचता है। उससे व्यग्र होकर ट्रंप उग्र प्रतिक्रिया जताते हैं। लेकिन उससे वे विपरीत संदेश दुनिया को दे रहे हैं। हर विवेकशील देश इससे सोचने को मजबूर हो रहा है कि जब हर डील ट्रंप का भविष्य ट्रंप के मूड से जुड़ा है, तो आखिर उसके लिए कितनी हांव-पांव मारी जाए?

United by Unique: व्यक्ति-केंद्रित दृष्टिकोण से कैंसर देखभाल की नई कहानी

डॉ. प्रदीप चंद्राकर, प्रोफेसर क्षेत्रीय कैंसर संस्थान

डॉ. मंजूला बेक, विभागाध्यक्ष, क्षेत्रीय कैंसर संस्थान

4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस है। जिसकी थीम है "united by unique" जिसका मतलब है, कैंसर का हर अनुभव अनूठा (unique) होता है और एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए हम सभी को एकजुट (united) होना होगा, जहाँ हम बीमारी से परे देखें और मरीज से पहले उस इंसान को समझें। इस विश्व कैंसर दिवस पर, आइए कैंसर देखभाल के भविष्य को फिर से लिखने के लिए हम एक साथ आएं, एक ऐसा भविष्य जहाँ लोगों और समुदायों की जरूरतें सबसे ऊपर हों।

"कैंसर" केवल एक मेडिकल डायग्नोसिस या रोग की पहचान मात्र नहीं है। यह एक अत्यंत व्यक्तिगत मामला है। हर डायग्नोसिस के पीछे एक अनूठी मानवीय कहानी छिपी होती है। दुख दर्द, उपचार, लचीलेपन, प्रेम और बहुत कुछ की कहानियाँ। यही कारण है कि कैंसर देखभाल के लिए 'पीपल सेंटर्ड' (व्यक्ति केंद्रित) दृष्टिकोण, जो करुणा और सहानुभूति के साथ प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरी तरह से एकीकृत करता है, स्वास्थ्य के सर्वोत्तम परिणामों की ओर ले जाता है।

यह अभियान व्यक्ति-केंद्रित कैंसर देखभाल के विभिन्न आयामों और बदलाव लाने के नए तरीकों का पता लगाने के लिए एकजुट प्रयास है, जिसमें पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर का क्षेत्रीय कैंसर संस्थान, जो कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र शासकीय कंप्रिहेंसिव कैंसर सेंटर है, यह जागरुकता बढ़ाने से लेकर कैंसर के ईलाज के लिए ठोस कदम के लिए प्रतिबद्ध है। इस आयोजन के तहत आज संस्थान में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यकम की शुरुआत सुबह जागरूकता रैली एवं मैराथन से किया जायेगा, उसके बाद विभाग में निःशुल्क कैंसर जाँच शिविर आयोजित है जो प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक है।

क्षेत्रीय कैसर संस्थान रायपुर में कैंसर के इलाज की सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर उच्चतम स्तर की कैंसर की सिकाई से लेकर कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, पैलिएटिव केयर, बाल्य एवं शिशु कैंसर केयर की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। सभी तरह के कैंसर मरीज, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से लेकर आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग, प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक के मरीज यहाँ निःशुल्क स्वास्थ लाभ लेते हैं। यदि हम कैंसर आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2003 में नए मरीजों की संख्या 1601 थी, 2025 में बढ़कर लगभग 2 से 3 गुना, 35 सौ से 4 हजार तक हो गयी है। जहां 2003 में मात्र 3500 मरीज फॉलोअप के लिए आते थे, अब लगभग ढाई लाख से 3 लाख मरीज आते हैं।

पहले विभाग में कैंसर सिकाई के लिए मात्र टेलीकोबाल्ट एवं ब्रेकीथेरेपी की सुविधा भर थी, आज अत्याधुनिक मशीन एवं तकनीक जैसे IMRT, IGRT, VMAT की सुविधा उपलब्ध है जिससे कैंसर की PINPOINT सिकाई की जाती है एवं शरीर की सामान्य ऊतकों का अधिक से अधिक सुरक्षा कर पाना संभव है। अभी कैंसर सिकाई के लिए आने वाले मरीजों की संख्या 475 प्रतिवर्ष से बढ़कर 25000 है। यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र संस्थान है जहां इंटरस्टियल इम्प्लांट के माध्यम से ब्रेकीथेरेपी (BRACHYTHERAPY) की जाती है जिममें मुख एवं गले का कैंसर, पेनिल कैंसर (PENILE CANCER), सारकोमा इत्यादि प्रमुख हैं।

कैंसर में अधिकांश मरीज एडवांस अथवा अंतिम अवस्था में पहुंचते हैं, जिसमें कीमोथेरेपी अनिवार्य हो जाता है। संस्थान में 1 हजार से लेकर लाखों की कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। इसमें सामान्य कीमोथेरेपी से लेकर, पॉलीमर बाउंड, नैनोपार्टिकल, पेगीलटेड फॉर्म सम्मिलित हैं। वर्ष 2003 में कीमोथेरेपी लेने वालों की संख्या मात्र 2055 थीं जो 2025 में बढ़कर लगभग 24000 प्रतिवर्ष हो गई है। इसके अलावा मरीजों को जरुरत के अनुरूप इम्यूनोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी भी दी जाती हैं। चूँकि प्रत्येक मरीज अलग है, संस्थान का प्रयास रहता है उनका इलाज भी अनोखा हो।

कैंसर के प्रत्येक अवस्था में पैलिएटिव केयर की आवश्यकता होती है। पैलिएटिव केयर में सामान्य लक्षणों के निदान एवं उपचार के अलावा भावनात्मक सहयोग, सामजिक एवं पारिवारिक सहयोग की आवश्यकता होती है जिसका ध्यान संस्थान में सभी अवस्था के मरीजों के लिए रखा जाता है। विभाग में पैलिएटिव केयर हेतु 30 बेड का अलग से वार्ड है. दर्द की श्रेणी के अनुसार मरीजों का इलाज किया जाता है, दर्दनिवारक के रूप में सामान्य पैरासिटामोल से लेकर वीक/स्ट्रांग ओपिओइड्स (WEAK/STRONG OPIOIDS), मॉर्फिन की सुविधा है। वर्ष 2003 में मात्र 1312 मॉर्फिन टेबलेट दी जाती थी जो 2025 में बढ़कर लगभग 20000 हो गयी।

वर्ष 2014 में विभाग में कैंसर सर्जरी की सुविधा है, प्रतिवर्ष लगभग 500 से 700 मरीजों की निःशुल्क सर्जरी की जाती है, यहाँ सामान्य सर्जरी के अलावा, मिनिमल इनवेसिव सर्जरी हाईपेक व पाईपेक (HIPAC, PIPAC) भी की जाती है।

बाल्य एवं शिशु कैंसर केयर कठिन है, उन मरीजों अलग रूप से विशेष केयर की जरुरत पड़ती जिसमें उनके मानसिक दशा, डाईट, नार्मल ग्रोथ का भी ध्यान रखना जरुरी होता है। विभाग में बाल्य एवं शिशु कैंसर हेतु वर्ष 2018 में, अलग से ओपीडी एवं वार्ड संचालित हैं, जहां उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। अब तक लगभग 1000 मरीज स्वास्थ लाभ ले चुके हैं।

कैंसर देखभाल: जागरूकता से इलाज तक

करीब 10 साल पहले (लगभग 2015) कैंसर को लेकर सार्वजनिक जागरूकता सीमित थी। लोग इस विषय पर खुलकर बात करने से डरते थे और समाज में इससे जुड़ी भ्रांतियां अधिक थी। उस समय कैंसर जांच (स्क्रीनिंग) के बारे में जानकारी कम थी, जिसके कारण जांच कराने वालों की संख्या भी सीमित रहती थी। जानकारी के मुख्य स्रोत डॉक्टर, टीवी और पोस्टर हुआ करते थे। इलाज को लेकर आम धारणा यह थी कि कैंसर का मतलब सिर्फ कीमोथेरेपी या रेडिएशन है। रोकथाम को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। सही और विस्तृत जानकारी का भी अभाव था।

इसके विपरीत आज की स्थिति में कैंसर को लेकर खुली चर्चा हो रही है। अब जल्दी पहचान और स्क्रीनिंग पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जानकारी के स्रोतों में बड़ा बदलाव आया है। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया प्रमुख माध्यम बन चुके हैं। इलाज के क्षेत्र में भी व्यापक प्रगति हुई है, जहाँ अब इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी जैसे आधुनिक विकल्प उपलब्ध हैं। रोकथाम को महत्वपूर्ण माना जाने लगा है, विशेष रूप से ऌढश वैक्सीनेशन और स्वस्थ जीवनशैली पर जोर है। हालांकि जानकारी की उपलब्धता बढ़ी है, लेकिन इसके साथ ही गलत जानकारी और अफवाहें भी बढ़ी हैं, जो एक नई चुनौती के रूप में सामने आई हैं।

डॉ. विवेक चौधरी, डीन. पं. नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर

क्षेत्रीय कैंसर संस्थान में आधुनिक तकनीक, अनुभवी चिकित्सक दल और समग्र उपचार सुविधाओं के माध्यम से राज्य के प्रत्येक कैंसर मरीज तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाने का सतत प्रयास किया जा रहा है। कैंसर को लेकर किसी भी प्रकार की भ्रांतियों से दूर रहें, समय पर जांच कराएं, रोकथाम को अपनाएं और केवल प्रमाणित एवं विश्वसनीय चिकित्सा संस्थानों से ही जानकारी प्राप्त करें। जागरूकता, समय पर पहचान और सही इलाज ही कैंसर से लड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है।

डॉ. संतोष सोनकर, अधीक्षक, डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर

HPV वैक्सीनेशन: 2015 में इसके बारे में जानकारी न के बराबर थी, लेकिन आज यह गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर (Cervical Cancer) से बचाव के लिए एक सशक्त माध्यम बन चुका है। आज हल्ड की गाइडलाइंस हैं।

टेलीमेडिसिन और ऐप्स: आज मेटास्टेटिक कैंसर जैसी स्थितियों के लिए मरीज घर बेठे विशेषज्ञों से राय ले सकते हैं, जो 10 साल पहले संभव नहीं था।

जीनोमिक टेस्टिंग: अब इलाज सिर्फ वन साइज फिट्स ऑल' नहीं रहा। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के जरिए मरीज के जेनेटिक प्रोफाइल के आधार पर सटीक इलाज किया जा रहा है। गलत जानकारी (Infodemic): जहाँ इंटरनेट ने जागरूक किया है, वहीं चमत्कारी घरेलू नुस्खों जैसे भ्रामक दावों ने जोखिम भी बढ़ाया है। हमेशा विश्वसनीय संस्थाओं की जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए।

लोकलुभावन की बजाय आर्थिक सेहत ठीक करने वाला बजट

उमेश चतुर्वेदी

अंग्रेजी में एक मुहावरा है, टू रॉब पीटर टू पे पॉल। हिंदी में इसका मतलब होगा, पीटर से लेकर पॉल को देना। दुनिया की हर सरकारों के बजट के लिए इस मुहावरे का बखूबी इस्तेमाल होता है। मीडिया भी हर बजट के दिन एक खबर जरूर बनाता है, रूपया आएगा कहां से और जाएगा कहां। इसका भी मतलब इस मुहावरे जैसा ही। बजट प्रबंधन में दुनियाभर की सरकारें एक व्यक्ति या स्रोत से लेकर दूसरे को उपलब्ध कराती रही हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हर बजट ऐसा ही होता है। लोकसभा में साल 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट को इस मुहावरे से कुछ हद तक दूर रखा जा सकता है। बजट प्रस्तावों की मीमांसा होती रहेगी, लेकिन फौरी तौर पर देखें तो कुछ चीजें साफ होती हैं। इस बजट के बारे में कह सकते हैं कि यह लोकलुभावन नहीं है।

साल 2024-25 और 2025-26 के बजट को देखें तो उन दिनों मोदी सरकार पर जनता से किए गए वायदों को पूरा करने का दबाव था। इसलिए बीते दोनों बजट में लोकलुभावन घोषणाएं की गईं। वैसे भारतीय राजनीति की रवायत बन चुकी है कि ऐन चुनावों से पहले आने वाले बजट प्रस्तावों में उस राज्य विशेष जहां चुनाव होने हैं, के लिए लुभावनी घोषणाओं की बाढ़ आ जाती है। कुछ ही महीनों बाद पांच महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल पर बीजेपी जहां कब्जे की कोशिश में दिन-रात एक किए हुए हैं, वहीं प्रश्न प्रदेश बने तमिलनाडु में भी अपनी ताकतवर उपस्थिति जताने के लिए जोर लगाए हुई है। तमिलनाडु के पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में भी चुनाव होने हैं। इसी तरह बीजेपी की कोशिश गॉडह्लस ओन कंट्री यानी भगवान के अपने घर केरल में कमल का फूल खिलाने की है। जबकि असम में तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए मुतमइन है। राजनीतिक रवायत के मुताबिक, मौजूदा बजट प्रस्तावों में इन राज्यों के लिए घोषणाओं की बाढ़ आनी चाहिए थी। लेकिन तमिलनाडु से आने वाली निर्मला सीतारमण ने अपने नौंवे बजट में ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस लिहाज से यह बजट भारतीय राजनीति का नया चेहरा प्रस्तुत कर रहा है।

इस बजट के बारे में कहा जा सकता है कि यह लोकलुभावन घोषणाओं की बजाय संरचनात्मक सुधारों, विनिर्माण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जैसे भविष्य के क्षेत्रों पर केंद्रित है। इस बजट में जिस तरह शी मार्ट के जरिए महिला उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देने की बात है, बेकार और अनुपयोगी हो चुके कानूनों को बदलने के लिए समिति बनाने का का प्रस्ताव है या सात हाईस्पीड रेल कॉरीडोर बनाने की बात है या फिर ग्रामीण बजट को बढ़ावा दिया गया है, या फिर मनरेगा की जगह पर आए नए कानून जी राम जी को जबरदस्त प्रोत्साहन दिया गया है, उस वजह से यह बजट अलग स्वरूप लिए हुए दिख रहा है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने इसे वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका को सशक्त बनाने वाला बजट बताया है। हालांकि पूर्व वित्त मंत्री और अर्थशास्त्री पी चिदंबरम् मानते हैं कि इस बजट प्रस्ताव में सरकार चीन और अमेरिकी दबाव में दिख रही है।

लेकिन विदेशी समाचार माध्यमों और समाचार एजेंसियों की नजर में यह बजट एक तरह से क्रांतिकारी है। दुनिया की जानी-मानी आर्थिक समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग का कहना है कि भारत ने अपने बजट में $133 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर दांव लगाया है। इसके जरिए भारत अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सुपरचार्ज करने की तैयारी में है। इसके साथ ही ब्लूमबर्ग ने बजट में 12.2 लाख करोड़ के कैपेक्स को ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए बड़ा संकेत माना है। दुनिया की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने इन बजट प्रस्तावों को लेकर कहा है कि भारत के इस बजट में वित्तीय अनुशासन बनाम विकास का द्वंद्व दिख रहा है। एजेंसी कहती है कि बजट प्रस्ताव में मोदी सरकार ने 4.3 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा है। इसी तरह उसने बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाया। मोदी सरकार के ये कदम नए बदलाव के प्रतीक हैं। ब्रिटेन से प्रकाशित होने वाले प्रसिद्ध आर्थिक अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने मोदी सरकार के बजट को लेकर कहा है कि यह ग्लोबल अनिश्चितता के बीच भारत का स्थिर कदम है। इस बजट के जरिए भारतीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेश और राजकोषीय विवेक के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है। दुनिया की जानी-मानी पत्रिका फोर्ब्स ने 2026 के बजटको लेकर एक तरह से हैरत जताते हुए सवाल पूछ लिया है कि क्या सेमीकंडक्टर और एआई के क्षेत्र मे निवेश भारत को टेक्निकल दुनिया का सुपरपावर बनाएगा? दुनिया की दूसरी बड़ी समाचार एजेंसी एएफपी ने भारत के बजट में बुनियादी ढांचे के लिए रिकॉर्ड 133 अरब डॉलर देने के वादे का स्वागत किया है। कुछ ऐसी ही प्रतिक्रियाएं दूसरी संस्थाओं की भी है। मशहूर रेटिंग एजेंसी मूडीज ने इस बजट को 'टैक्टिकल' यानी रणनीतिक करार दिया है। मूडीज का मानना है कि यह बजट क्रेडिट प्रोफाइल में तुरंत बदलाव नहीं करेगा, लेकिन भारत की आर्थिक स्थिरता के लिए अच्छा है। इन प्रतिक्रियाओं में प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया को भी जोड़ सकते हैं, जिन्होंने इसे रिफॉर्म एक्सप्रेस बताया है।

भारतीय मध्य वर्ग को हर बार बजट से बड़ी उम्मीद रहती है। देश का सबसे बड़ा आयकर दाता मध्य वर्ग ही है। उसे उम्मीद थी कि इस बार के बजट में आयकर पर किंचित ही सही, छूट मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे उसे थोड़ी निराशा तो जरूर हुई है। बीबीसी और अल जजीरा जैसे चैनलों ने इस मुद्दे को अपनी रवायत के मुताबिक अपनी समीक्षाओं में प्रमुखता दी है। दोनों ही समाचार संस्थानों ने भारतीय विपक्षी नेताओं और आर्थिक-तकनीकी विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है कि आयकर स्लैब में बदलाव न होने से मध्यम वर्ग को उतनी राहत नहीं मिली, जितनी उम्मीद थी। सरकारी कमर्चारी उम्मीद कर रहे थे कि आठवें वेतन आयोग को लेकर भी बजट में कोई बड़ी चर्चा या ऐलान हो सकता है। लेकिन निर्मला सीतारमण ने इससे परहेज किया।

इसका यह मतलब नहीं कि बजट में आम आदमी का ध्यान नहीं रखा गया है। बजट में कुछ बेहतरीन घोषणाएं भी हुई हैं। महिला उत्थान और सशक्तीकरण की बात खूब की जाती है, लेकिन गांवों या छोटे शहरों से बड़े शहरों में पढ़ाई या नौकरी के लिए आने वाली लड़कियों की सहूलियतों पर कम ही ध्यान दिया जाता रहा है। लेकिन इस बार बजट में उनका ध्यान रखा है। बजट में हर जिले में महिला छात्रावास बनाने का प्रस्ताव किया गया है। बजट का यह फैसला लड़कियों को कॉलेज और नौकरियों तक पहुंचाने में बहुत मददगार साबित होगा। मां-बाप भी बिना किसी डर के सरकारी हास्टलों में अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए भेज सकेंगे। इससे न केवल पढ़ाई बीच में छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या कम होगी, बल्कि लड़कियां खुद को ज्यादा सुरक्षित और आत्मनिर्भर महसूस करेंगी। पढ़ाई के साथ-साथ जो अपना छोटा-मोटा काम करने या स्टार्टअप चलाने वाली महिलाओं के लिए भी बजट में घोषणा हुई है। सरकार ने 'शी मार्ट्स' नामक प्लेटफॉर्म शुरू करने का फैसला किया है। ये ऐसे बाजार या प्लेटफॉर्म होंगे, जहां सिर्फ महिला उद्यमी, स्वयं सहायता समूह और महिला कारीगर ही अपना सामान बेच सकेंगी। इससे महिलाओं को बिचौलियों की जरूरत नहीं रहेगी। इसी तरह कैंसर के इलाज वाली 17 दवाओं के साथ ही शुगर की दवाओं पर कर में कमी की गई है। साथ ही सात दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए बाहर से आयात होने वाली दवाओं और स्पेशल फूड पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे उन्हें बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी जो इलाज के लिए महंगी विदेशी दवाओं पर निर्भर हैं। भारत को बायोफार्मा का हब बनाने का भी ऐलान किया गया है। ग्रामीण विकास पर दो लाख 73 हजार 108 करोड़ और कृषि एवं कृषि विकास पर एक लाख 62 हजार 671 करोड़ के बजट का प्रस्ताव ग्रामीण क्षेत्रों की रौनक बढ़ा सकता है।

सस्ती तकनीक और हर नागरिक तक पहुंच: एआई में आत्मनिर्भर भारत की तैयारी

सुशील पाल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संयुक्त सचिव

कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आज की सबसे ताकतवर और तेजी से बदलने वाली तकनीक में से एक बनती जा रही है। इसमें यह क्षमता है कि यह देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे, उत्पादन बढ़ाए और विकास की रफ्तार तेज करे। सरकारी सेवाओं को ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाने में भी एआई अहम भूमिका निभा सकती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बीमारी की शुरुआती पहचान, खेती में सही समय पर सही फैसले लेने, आपदा से पहले चेतावनी देने, मौसम और जलवायु का बेहतर अनुमान लगाने और सरकारी योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने में एआई पहले से ही मदद कर रही है। आने वाले समय में शिक्षा, परिवहन और उद्योग जैसे क्षेत्रों में भी एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ने की संभावना है।

लेकिन जैसे पहले की तकनीकी क्रांतियों में हुआ, वैसे ही एआई के साथ भी असमानता की तस्वीर सामने आती है। जिनके पास कंप्यूटर की ताकत यानी कंप्यूट, अच्छा डेटा और मजबूत डिजिटल ढांचा है, वही बड़े स्तर पर एआई का लाभ उठा पा रहे हैं। जिनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं, वे पीछे रह जाते हैं। यह फर्क आज केवल कंपनियों के बीच ही नहीं, बल्कि देशों और इलाकों के बीच भी साफ दिखाई देता है। भारत ने इस चुनौती को एक अवसर के रूप में लिया है। इंडिया एआई मिशन के जरिए भारत यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि एआई की ताकत कुछ गिने-चुने लोगों तक सीमित न रहे। कंप्यूट, डेटा और एआई मॉडल को डिजिटल सार्वजनिक सुविधा के रूप में देखा जा रहा है, ताकि स्टार्टअप, शोधकर्ता, छात्र और छोटे संस्थान भी एआई पर काम कर सकें। भारत की सोच साफ है- ऐसा डिजिटल ढांचा बनाया जाए जो खुला हो, आसानी से बढ़ सके और समाज के हर वर्ग के काम आए। इससे एआई का लाभ आम लोगों तक पहुंचे, देश में ही नवाचार को बढ़ावा मिले और तकनीक के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन सके। इस सोच के पीछे एक ठोस योजना है। दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत एआई को पांच स्तरों पर विकसित कर रहा है- बिजली और ऊर्जा, कंप्यूट और इंफ्रास्ट्रक्चर, चिप और हाडवेंयर, एआई मॉडल और एप्लिकेशन। इन सभी पर एक साथ काम होने से ही एआई का सही और व्यापक उपयोग संभव हो पाएगा।

भारत का तरीका इसलिए अलग है क्योंकि यहां एआई तक पहुंच आसान बनाई गई है। भारत ने एक साझा कंप्यूट प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जहां 38,000 जीपीयू एक ही पोर्टल पर मिलते हैं। इनका खर्च करीब 65 रुपये प्रति घंटा है, जबकि दूसरे देशों में इसके लिए 2.5 से 3 डॉलर प्रति घंटा तक देने पड़ते हैं। इंडिया एआई मिशन के तहत सरकार एआई मॉडल बनाने के लिए पूरी लागत (100 प्रतिशत) तक मदद दे रही है और एआई के इस्तेमाल पर भी 40 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। इससे पैसे की कमी एआई पर काम करने में रुकावट नहीं बनती। इसी वजह से सरवम एआई, सोकेट एआई और ज्ञानि एआई जैसे भारतीय स्टार्टअप अब बिना बड़ी पूंजी लगाए अपने खुद के एआई और भाषा मॉडल बना पा रहे हैं, जो पहले सिर्फ बड़ी विदेशी कंपनियां ही कर पाती थीं। भारत का लक्ष्य सिर्फ एआई का इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि अपना एआई बनाना है। भारत अपना खुद का एआई मॉडल तैयार कर रहा है, जो भारतीय भाषाओं, भारतीय संस्कृति और भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। इसे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट (16-20 फरवरी 2026) में पेश किए जाने की उम्मीद है। यह मॉडल भारत के ही डेटा पर प्रशिक्षित होगा और देश के भीतर ही काम करेगा। इससे एआई ज्यादा सटीक, निष्पक्ष और सबको साथ लेकर चलने वाला बनेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित होगा कि डेटा सुरक्षित रहे और एआई का इस्तेमाल देश के कानूनों और नागरिकों के अधिकारों के अनुसार हो। भारत का यह तरीका उन देशों के लिए भी एक उदाहरण है, जो अभी विकास के रास्ते पर हैं। यह दिखाता है कि खुलेपन और नवाचार के साथ-साथ अपनी तकनीकी स्वतंत्रता कैसे बनाए रखी जा सकती है। भारत अपने एआई मॉडल ओपन-सोर्स के रूप में विकसित कर रहा है, ताकि दूसरे देश भी अपनी जरूरतों के अनुसार इन्हें अपना सकें। मकसद है मिलकर आगे बढ़ना, बिना किसी नई निर्भरता के। आज जब एआई देश की ताकत और अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा बन चुकी है, सवाल यह नहीं रह गया है कि एआई अपनाया जाए या नहीं, बल्कि यह है कि इसे समझदारी, जिम्मेदारी और टिकाऊ तरीके से कैसे अपनाया जाए।

खास खबर

बजट में सहकारिता क्षेत्र को बड़ी सौगात, किसानों को मिलेगा लाभ : प्रीतपाल

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

भारत की अर्थव्यवस्था में सहकारिता की भूमिका को इस वर्ष के केन्द्रीय बजट में सशक्त और औपचारिक मान्यता दी गई है। यह बजट इसलिए विशेष माना जा रहा है क्योंकि इसमें सहकारी संस्थाओं को कृषि, ग्रामीण विकास और किसान कल्याण की केन्द्रीय एवं महत्वपूर्ण इकाइयों के रूप में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। बजट ज्ञापन में सहकारिताओं के लिए दिए गए विशेष लाभों हेतु समर्पित खण्ड शामिल किया गया है, वहीं वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में भी सहकारिता क्षेत्र की भूमिका और महत्व को प्रमुखता से रेखांकित किया।

दुर्ग जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन ने कहा कि यह बजट किसानों और सहकारी समितियों की जमीनी वास्तविकताओं की गहरी समझ को दर्शाता है। इसी क्रम में एक अहम सुधार के तहत प्राथमिक सहकारी समितियों को आयकर में कटौती की सुविधा प्रदान की गई है, जो अपने सदस्यों द्वारा उत्पादित कपास बीज एवं पशु आहार की आपूर्ति करती हैं। कपास की खेती और डेयरी गतिविधियां ग्रामीण आजीविका के प्रमुख साधन हैं तथा पशु आहार और कपास बीज इन क्षेत्रों के अत्यंत महत्वपूर्ण इनपुट हैं। इस कटौती से प्राथमिक सहकारी समितियों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और इसका सीधा लाभ बेहतर कीमतों, बेहतर सेवाओं और सशक्त संस्थानों के रूप में किसानों तक पहुंचेगा।

अब उन प्राथमिक सहकारी समितियों को भी लाभ एवं आय में कटौती की सुविधा मिलेगी, जो संघीय सहकारी समिति, सरकारी संगठनों आदि को पशु आहार और कपास बीज की आपूर्ति करती हैं। वतर्मान में यह सुविधा दूध, तिलहन, फल एवं सब्जियों की आपूर्ति करने वाली समितियों को ही प्राप्त थी। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी समितियों को आयकर अधिनियम की धारा 2(32) के तहत सहकारी समिति की परिभाषा में शामिल किया जाएगा। यह संशोधन 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा और कर वर्ष 2026-27 से लागू होगा।

नई कर व्यवस्था के तहत सहकारी समितियों को अन्य सहकारी समितियों से प्राप्त लाभांश आय पर कर कटौती की अनुमति दी गई है, बशर्ते यह लाभांश आगे अपने सदस्यों को वितरित किया जाए। इससे सहकारी ढांचे में दोहरी कराधान की समस्या समाप्त होगी और आय सीधे सदस्यों तक पहुंचाने को प्रोत्साहन मिलेगा।

समग्र रूप से यह बजट एक सशक्त संदेश देता है कि देश में सहकारिताओं का महत्व तेजी से बढ़ा है और अब इसे नीति स्तर पर पूरी तरह स्वीकार किया गया है। स्पष्ट कानूनी मान्यता, निष्पक्ष कर व्यवस्था और लक्षित प्रोत्साहन अधिक से अधिक सहकारी समितियों को आगे आने, अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करने और देशभर में व्यवसाय बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। अंततः इससे सहकारी आंदोलन मजबूत होगा और सामान्य किसान समुदाय का समग्र उत्थान सुनिश्चित होगा।

कमिश्नरेट का सामुदायिक पुलिसिंग अभियान संवाद से समाधान शुरू

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग को सशक्त बनाने के उद्देश्य से संवाद से समाधान अभियान का आगाज किया गया है। इस अभियान की शुरुआत सेंट्रल जोन अंतर्गत तेलीबांधा क्षेत्र की बीएसयूपी कॉलोनी से की गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र को नशा-मुक्त बनाना, अपराधों की रोकथाम करना और पुलिस एवं आम नागरिकों के बीच विश्वास व संवाद को मजबूत करना रहा। यह सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) सेंट्रल जोन उमेश गुप्ता के निर्देशन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त तारकेश्वर पटेल, सहायक पुलिस आयुक्त (सिविल लाइंस) रमाकांत साहू तथा थाना प्रभारी तेलीबांधा अविनाश सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। पुलिस अधिकारियों ने कॉलोनीवासियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।

कार्यक्रम के दौरान नागरिकों को रायपुर पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था की विशेषताओं की जानकारी दी गई। साथ ही नशे के दुष्परिणामों पर विस्तार से चर्चा करते हुए युवाओं और आम नागरिकों से नशे से दूर रहने तथा समाज को नशा-मुक्त बनाने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई। अधिकारियों ने बताया कि नशा अपराध की जड़ है और इसके खिलाफ सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। इसके अलावा, नागरिकों को मोटर व्हीकल नियमों के पालन के महत्व, सड़क सुरक्षा, हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग, तेज रफ्तार और शराब पीकर वाहन चलाने के खतरों से भी अवगत कराया गया। साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों को देखते हुए साइबर फ्रॉड से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई और किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक या ऑनलाइन ठगी की तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की गई।

पुलिस अधिकारियों ने किरायेदार सत्यापन को अनिवार्य बताते हुए कहा कि मकान मालिकों को अपने किरायेदारों का सत्यापन अवश्य कराना चाहिए, ताकि असामाजिक तत्वों की पहचान समय रहते हो सके। साथ ही क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि या संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस को देने पर जोर दिया गया। संवाद सत्र के दौरान स्थानीय नागरिकों ने भी अपनी समस्याएं खुलकर रखीं। कॉलोनी के किनारे की टूटी हुई दीवार, क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरों की आवश्यकता जैसे मुद्दे प्रमुखता से सामने आए। पुलिस अधिकारियों ने इन समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए संबंधित विभागों से समन्वय कर आवश्यक पहल करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में नागरिकों की सक्रिय सहभागिता देखने को मिली। लोगों ने पुलिस के इस प्रयास की सराहना करते हुए नशा-मुक्त और सुरक्षित मोहल्ला बनाने के लिए हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि संवाद से समाधान अभियान आगे भी सेंट्रल जोन सहित अन्य क्षेत्रों में लगातार जारी रहेगा, ताकि पुलिस और जनता मिलकर सुरक्षित, शांत और अपराध-मुक्त समाज का निर्माण कर सकें।

आयुक्त ने प्रस्तावित और नवीन पीएम आवास का किया निरीक्षण

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का निर्माण किया जाना है। आवास निर्माण हेतु अतिरिक्त स्थल की आवश्यकता को देखते हुए आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय द्वारा रिक्त स्थल का अवलोकन किया गया है।

निगम आयुक्त ने स्मृति नगर बुद्ध कालोनी, सूर्या विहार, हाउसिंग बोर्ड ढ़ाचा भवन सांई मंदिर के पास, कैलाश नगर भगवा चौक एवं प्रगति नगर में पीएम आवास हेतु रिक्त स्थल का अवलोकन किया है। उपस्थित तहसीलदार एवं पटवारी को सीमांकन कार्य जल्द पूर्ण करने कहा गया है। आयुक्त ने सूर्या विहार में निर्माणाधीन पीएम आवास का जायजा लिए। निर्माण कार्य में गुणवत्ता लाने और कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने निर्देशित किये है, जिससे हितग्राहियों को मकान प्रदाय किया जा सके। प्रगति नगर में पूर्व से खेल मैदान एवं नवीन सड़क निर्माण प्रस्तावित है। नागरिको की समस्याओं को देखते हुए कार्य जल्द प्रारंभ कराने निर्देशित किया गया है। निरीक्षण के दौरान कायर्पालन अभियंता कुलदीप गुप्ता, उप अभियंता दीपक देवांगन, आदित्य सिंह एवं अन्य अधिकारी कमर्चारी उपस्थित रहे।

फॉरेंसिक साइंस के छात्राओं ने थाना पुलगांव का किया शैक्षणिक भ्रमण

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

भारती महाविद्यालय के फॉरेंसिक साइंस (प्रथम वर्ष) के छात्र-छात्राओं द्वारा थाना पुलगांव में शैक्षणिक भ्रमण किया गया। इस भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों को अपराध की शिकायत से लेकर विवेचना तक की संपूर्ण प्रक्रिया की व्यवहारिक जानकारी प्रदान करना रहा।

भ्रमण के दौरान थाना पुलगांव के ड्यूटी अधिकारी एएसआई सुभाष साहू एवं प्रधान आरक्षक अभिषेक मिश्रा द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के अपराधों की प्रारंभिक शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, जांच अधिकारी द्वारा की जाने वाली विवेचना तथा अपराध की जांच से संबंधित विधिसम्मत कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ ही विद्यार्थियों को घटना स्थल पर पुलिस द्वारा की जाने वाली जांच प्रक्रिया, साक्ष्य संकलन एवं उनके संरक्षण की महत्वपूर्ण विधियों से भी अवगत कराया गया।

व्यावहारिक जानकारी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विद्यार्थियों को थाना परिसर स्थित बंदीगृह, विवेचक कक्ष, मालखाना एवं थाना प्रभारी कक्ष का अवलोकन भी कराया गया, जिससे उन्हें पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली को प्रत्यक्ष रूप से समझने का अवसर प्राप्त हुआ। इस शैक्षणिक भ्रमण के दौरान एएसआई सुभाष साहू एवं प्रधान आरक्षक अभिषेक मिश्रा द्वारा विद्यार्थियों को सरल, स्पष्ट एवं व्यवहारिक जानकारी प्रदान करने में सराहनीय भूमिका निभाई गई।

दुर्ग पुलिस का संदेश

दुर्ग पुलिस शैक्षणिक संस्थानों के साथ निरंतर समन्वय कर विद्यार्थियों को कानून, अपराध विवेचना एवं पुलिस कार्यप्रणाली की व्यवहारिक जानकारी देने हेतु प्रयासरत है, ताकि युवा वर्ग में विधिक जागरूकता एवं जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सके।

किसानों के हितों की रक्षा और खुशहाली के लिए सरकार प्रतिबद्ध और संकल्पित : सुरेंद्र

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक ने धान खरीदी की समय सीमा दो दिन बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है।

भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार के इस संवेदनशील निर्णय से उन किसानों को अपना धान विक्रय करने का अवसर मिलेगा, जो टोकन कटने के बाद भी अपना धान नहीं बेच पाए थे। इस निर्णय से प्रदेश सरकार धान खरीदी के अपने निर्धारित लक्ष्य को भी हासिल करेगी। श्री कौशिक ने कहा कि इस निर्णय के बेहतर परिणाम सामने आएंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने धान खरीदी केंद्रो पर बारदानो एवं हमालो की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिया है ताकि किसानों को कोई भी असुविधा न हो सके। श्री कौशिक ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों के सवर्तोमुखी हितों की रक्षा और उनकी खुशहाली के लिए हर कदम पर अपनी प्रतिबद्धता के साथ संकल्पित है।

जिला चिकित्सालय में कार्मिकों की कमी दूर करने कलेक्टर को सौंपा गया मांग पत्र

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

जिला चिकित्सालय में आवश्यक कामिर्कों की नियुक्ति की मांग को लेकर जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर अभिजीत सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। उल्लेखनीय है कि जिला चिकित्सालय 500 बिस्तरों की क्षमता के साथ संचालित है, जहां प्रतिदिन 1000 से अधिक मरीज उपचार हेतु पहुंचते हैं। स्थानीय मरीजों के साथ-साथ अन्य जिलों से भी विभिन्न रोगों से पीड़ित मरीज यहां चिकित्सा सेवाएं लेने आते हैं।

ज्ञापन में बताया गया कि चिकित्सालय में वाहन चालक, ड्रेसर एवं रेडियोग्राफर जैसे महत्वपूर्ण पद स्वीकृत होने के बावजूद अब तक नियुक्तियां नहीं की गई हैं। कामिर्कों की कमी के कारण अस्पताल में निर्धारित दायित्वों के निर्वहन एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिसका सीधा असर मरीजों की सुविधा और उपचार व्यवस्था पर पड़ रहा है।

इसी तारतम्य में जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने हेतु यह मांग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें शीघ्र नियुक्ति कर अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की मांग की गई। इस अवसर पर जीवन दीप समिति के आजीवन सदस्य दिलीप ठाकुर, सीताराम ठाकुर एवं रमेश साहू उपस्थित रहे।

दुर्ग पुलिस की नई पहल : मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए टोल फ्री नंबर 1933 किया जारी

ऑपरेशन विश्वास के तहत 500 ई-रिक्शा बने जन-जागरूकता का माध्यम

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

मादक पदार्थों एवं ड्रग्स के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा आम नागरिकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दुर्ग पुलिस द्वारा ऑपरेशन विश्वास के अंतर्गत टोल फ्री नंबर 1933 जारी किया गया है। इस नंबर के माध्यम से नागरिक नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों एवं गतिविधियों की सूचना सीधे पुलिस को दे सकेंगे।

दुर्ग पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि टोल फ्री नंबर 1933 पर सूचना देने वाले नागरिकों की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी तथा प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित एवं विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी, जिससे सूचना देने वालों में विश्वास और सुरक्षा की भावना बनी रहे।

जन-जागरूकता अभियान को व्यापक बनाने के उद्देश्य से बुधवार को दुर्ग-भिलाई शहर में संचालित लगभग 500 ई-रिक्शा में टोल फ्री नंबर 1933 चस्पा किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला दुर्ग विजय अग्रवाल द्वारा ई-रिक्शाओं को हरि झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके साथ ही जिले के समस्त पुलिस वाहनों में भी यह टोल फ्री नंबर प्रदर्शित किया गया है, ताकि अधिक से अधिक नागरिकों तक इसकी जानकारी पहुंच सके।

नशा मुक्त बनाने की दिशा में कदम

दुर्ग पुलिस का मानना है कि नशे के खिलाफ लड़ाई में जनसहभागिता बेहद जरूरी है। इस पहल से आम लोग बिना भय के अवैध नशे के कारोबार की जानकारी पुलिस तक पहुंचा सकेंगे, जिससे अपराधियों पर शिकंजा कसने में मदद मिलेगी। दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें मादक पदार्थों, ड्रग्स अथवा अन्य नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से संबंधित कोई भी जानकारी मिले, तो तत्काल टोल फ्री नंबर 1933 पर सूचना दें और समाज को नशा मुक्त बनाने के इस अभियान में पुलिस का सहयोग करें।

सौगात — 2 करोड़ 17 लाख 88 हजार से संवरेगी सड़क

दुर्ग ग्रामीण विधायक चंद्राकर ने रिसाली के सड़कों की मरम्मत करने चार वार्डों में किया भूमिपूजन

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने विकास कार्य के लिए भूमिपूजन किया। उन्होंने 2 करोड़ 17 लाख 88 हजार से होने वाली सड़क मरम्मत कार्य के लिए आमजनों को श्रेय देते बधाई दी। वें चार अलग-अलग वार्डों में आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रम शामिल हुए।

दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि वें हमेशा जनहित के कार्यो को पूर्ण कराने प्राथमिकता देते है। वतर्मान में शहर के खराब सड़कों को सूचबद्ध कर शासन स्तर पर कार्य को स्वीकृत कराया है। इसी का परिणाम है कि वें भूमिपूजन के बहाने क्षेत्रवासियों से रूबरू हो रहे है। उन्होंने कहा कि अब इस क्षेत्र के नागरिकों को साफ सुथरी सड़क मिलेगी। आवागमन में सुविधा होगी। इस दौरान विधायक ललित ने आम नागरिकों से चर्चा भी की। भूमिपूजन कार्यक्रम में सभापति केशव बंछोर, नेता प्रतिपक्ष शैलेन्द्र साहू, एमआईसी सनीर साहू, पार्षद सविता ढवस, सुनंदा दिपक पप्पू चंद्राकर, गजेन्द्री कोठारी, ममता सिन्हा, ईश्वरी साहू, सीमा साहू, धर्मेन्द्र भगत, सरिता देवांगन, मण्डल अध्यक्ष राजू जंघेल, अनूपम साहू समेत गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

जाने सड़क मरम्मत कार्य को

वार्ड 01 तालपुरी ब्लाक ए में लोटस 352 से 363 व 371 से 378 तक 41.12 लाख रूपए से

सड़क मरम्मत किया जाएगा। इसी तरह वार्ड 17 में शीतला तालाब से लालता प्रसाद घर व लालता प्रसाद घर से पंप हाऊस तक क्रमशः 45.06 व 42.12 लाख, वार्ड 27 मैत्रीनगर कान्हा जी घर से फैंसी स्टोर से व मैदान से डेंटल क्लीनिक तक 40.95 लाख, वार्ड 31 में हिंद नगर शिवा जी चैक से सुरेन्द्र देवांगन घर तक, नंद किशोर घर लक्ष्मी नगर चैक तक 48.63 लाख से सड़क मरम्मत कार्य किया जाएगा।

महिलाओं को मिला गैस सिलेण्डर

भूमिपूजन कार्यक्रम में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने वार्ड 31 रिसाली बस्ती में उज्वला योजना के तहत गैस वितरण किया। योजना का लाभ पूनम चतुर्वेदी, संजना चतुर्वेदी, टोमिन देशमुख, विमला कुर्रे, कांती साहू, रानी गायकवाड़, हेमलता, रूखमनी गायकवाड़, सुमन शर्मा, संध्या, मंजू यादव व अंजनी यादव ने लिया।

दुर्ग निगम में बजट निर्माण की प्रक्रिया शुरू, बजट समय सीमा में होगा प्रस्तुत

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

महापौर अलका बाघमार एवं आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देश पर नगर पालिक निगम दुर्ग में आगामी बजट की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। निगम प्रशासन द्वारा शहर के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों तथा पाषर्दों से बजट में शामिल किए जाने वाले विकास कार्यों के मांग एवं सुझावों के प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।

प्रस्ताव भेजने की समय-सीमा एक सप्ताह बढ़ाई गई निगम प्रशासन ने प्रस्ताव प्रस्तुत करने की समय-सीमा को एक सप्ताह के लिए बढ़ाया है, जिससे सभी विभाग एवं पार्षद अपने-अपने क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर और व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत कर सकें। अधिकारियों ने बताया कि इससे बजट अधिक लोकहित कारी और संतुलित बनाया जा सकेगा।

प्राप्त प्रस्तावों के संकलन के बाद निगम में बजट पर चर्चा बैठक आयोजित की जाएगी। आवश्यक संशोधन एवं औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात सभापति श्याम शर्मा की अध्यक्षता में सामान्य सभा का आयोजन कर बजट प्रस्तुत किया जाएगा।

वित्त प्रभारी नरेंद्र बंजारे ने बजट बैठक में हुई देरी को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि वतर्मान में एसआईआर मतदाता सूची के कार्य में नगर निगम के अधिकारी एवं कमर्चारियों की ड्यूटी लगी हुई है। इसी कारण निगम के कुछ आवश्यक कार्यों पर अस्थायी प्रभाव पड़ा है।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि समय-सीमा का पूरा ध्यान रखते हुए बजट बैठक शीघ्र आयोजित की जाएगी, ताकि नगर विकास से जुड़े कार्यों की गति में कोई बाधा न आए। निगम प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। बजट समय सीमा में प्रस्तुत किया जाएगा, यह बजट शहर के विकास कार्यों को नई दिशा देगा।

ब्लड प्रेशर व डायबिटीज के मरीजों के लिए वरदान है कद्दू

कद्दू एक ऐसी सब्जी के जिसे बच्चे से लेकर बड़े तक हर खाने में मुंह बनाता है। मगर एक्सपर्ट्स के अनुसार, यह गुणों से भरपूर होती है। इसमें कैल्शियम, आयरन, फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि गुण होते हैं। ऐसे में इसका सेवन करने से इम्यूनिटी स्ट्रांग होने से लेकर वजन घटाने में मदद मिलती है। इसके साथ ब्लड प्रेशर व डायबिटीज के मरीजों के लिए यह वरदानस्वरूप है। चलिए जानते हैं इसे खाने के बेहतरीन गुणों के बारे में

डायबिटीज में फायदेमंद

एक्सपर्ट्स के अनुसार, टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए कद्दू बेहद फायदेमंद मानी गई है। इसका सेवन करने से शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। ऐसे में डायबिटीज के मरीजों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए।

हाई बीपी रखे कंट्रोल

कद्दू में पोटैशियम भरपूर होता है। ऐसे में यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में कारगर माना जाता है। इसलिए ब्लड प्रेशर के मरीजों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए।

इम्यूनिटी करे स्ट्रांग

कद्दू में विटामिन-ए, सी, ई आदि गुण होते हैं। इसके सेवन से तेजी से इम्यूनिटी बढ़ती है। ऐसे में शरीर को बीमारियों से लड़ने की अंदर से मजबूती मिलती है। साथ ही सर्दी, जुकाम, मौसमी व अन्य बीमारियों की चपेट में आने का खतरा कई गुणा कम रहता है।

कब्ज से दिलाए राहत

गलत खानपान के चलते बहुत से लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है। ऐसे में इस समस्या से राहत पाने के लिए कद्दू का सेवन करना फायदेमंद माना जाता है। इसके बीजों में फाइबर होने से पाचन शक्ति तेज होती है। ऐसे में कब्ज व पेट संबंधी अन्य समस्याओं से बचाव रहता है।

आंखों के लिए फायदेमंद

इसमें बीटा कैरोटीन होता है। ऐसे में यह आंखों के लिए स्वस्थ माना जाता है। इसके सेवन से आंखों की रोशनी बढ़ने के साथ इससे जुड़ी समस्याएं होने से बचाव रहता है।

हड्डियों होगी मजबूत

कद्दू में कैल्शियम उचित मात्रा में होता है। ऐसे में इसका सेवन करने हड्डियां मजबूत होती है। इसके साथ ही ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम रहता है। इसलिए बच्चे से लेकर बड़ों तक हर उम्र के लोगों को इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए।

वजन घटाए

इसका सेवन करने से वजन कम करने में भी मदद मिलती है। ऐसे में मोटापे से परेशान लोगों को इसे अपनी डेली डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए।

हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने में मदद करती हैं ये चीजें

हीमोग्लोबिन शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन देता है। शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ाने के लिए कई सारी चीजों को डाइट में शामिल किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं ऐसे नट्स के बारे में जो आयरन की कमी को पूरा करेंगे और आपके हीमोग्लोबिन को तुरंत बढ़ाएंगे।

शरीर को फिट रखने में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स खाना बेहद जरूरी है। यदि किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो यह शरीर के लिए परेशानी का कारण बनने लगता है। अक्सर लोगों में हीमोग्लोबिन ऐसे में आयरन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए महत्तवपूर्ण है। शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ाने के लिए कई सारी चीजों को डाइट में शामिल किया जा सकता है।

काजू

अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो आप काजू खा सकते हैं। ये आपकी भूख को कम करता है साथ ही शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं। एक मुट्ठी काजू में 189 मिली ग्राम आयरन होता है। ऐसे में जंक फूड खाने से अच्छा है कि आप स्नैक्स में एक मुट्ठी काजू का सेवन करें।

पिस्ता

पिस्ता स्वाद से भरपूर है और स्नैक्स के लिए सबसे अच्छा है। अगर आपको आयरन की कमी है तो एक मुट्ठी पिस्ता खाएं। एक मुट्ठी पिस्ता में 1.11 मिली ग्राम आयरन होता है।

बादाम

भिगे बादाम खाने से शरीर को कई तरह के पोषक तत्व मिलते हैं। अगर आप एक मुट्ठी बादाम का सेवन करते हैं तो आपको 1.05 मिली ग्राम मिलता है। कई लोग बादाम का दूध और बादाम के बटर का सेवन करते हैं। ऐसे आपको रोजाना बादाम का सेवन करना चाहिए।

अखरोट

अखरोट में सबसे ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। ये आपके दिमाग को शार्प करने में मदद करता है। साथ ही कम हीमोग्लोबिन वाले लोगों को रोजाना अखरोट का सेवन करना चाहिए। एक मुट्ठी अखरोट खाने से आपको 08 मिली ग्राम प्रोटीन मिलता है।

मुंगफली

अगर आप मेवा नहीं खा सकते है, तो आप मुंगफली का सेवन कर सकते हैं। एक मुट्ठी मुंगफली में 13 मिलीग्राम मिनीरल्स होते है।

बेजोड़ सुंदरता और स्वास्थ्य चाहिए, तो रोजाना पिएं एक गिलास नोनी फ्रूट जूस

यंग दिखने के लिए अब आपको रॅपन्जेल के बालों की जरूरत नहीं है। इसके बजाय, एक गिलास नोनी फ्रूट जूस आपकी मदद कर सकता है। हम जानते हैं कि यह फल आपके लिए नया है, लेकिन आयुर्वेद में भी इस अद्भुत फल का उल्लेख किया गया है। आजकल जहां रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, वहां नोनी फल आपकी मदद कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह फल पोषक तत्वों से भरा हुआ है जो न केवल शरीर की कोशिकाओं के पुनर्जनन में मदद करता है, बल्कि विभिन्न वायरस द्वारा हुए नुकसान की मरम्मत में भी मदद करता है। नोनी फल विटामिन ए, विटामिन इ, विटामिन डी3 और आयरन जैसे एंटीऑक्सिडेंट का एक पावरहाउस है। यह सब न केवल आपके आंतरिक कल्याण के लिए, बल्कि बाहरी सुंदरता के लिए भी फायदेमंद हैं। नोनी फल के स्वास्थ्य लाभ

- नोनी फ्रूट जूस पीने से ब्लड शुगर लेवल बनाए रखने में मदद मिलती है
- नोनी फल में एंटीऑक्सिडेंट के साथ-साथ जीवाणुरोधी और एंटीफंगल गुण होते हैं जो इसे आपकी त्वचा के लिए बहुत अच्छा बनाते हैं। नोनी फ्रूट जूस पीने से न केवल आपके रक्त को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है, बल्कि यह आपके पेट के स्वास्थ्य को भी नियंत्रित रखता है। यह सब बेहतर कोशिका संरचना और चिरस्थायी सौंदर्य की ओर ले जाता है।
- **यह जोड़ों की समस्याओं को दूर करता है**
  गठिया से जूझ रहे लोग दर्द का सही अर्थ जानते हैं। आखिरकार, वे दिन-ब-दिन इससे गुजरते हैं। इसके अलावा, इस रोग से संबंधित विकृतियां और भी अधिक समस्याग्रस्त हैं। लेकिन अगर आप अपने दैनिक आहार में नोनी फ्रूट जूस को शामिल करते हैं, तो आप इस समस्या से अच्छी तरह निपट सकते हैं, जैसा कि फूड्स जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है।
- **नोनी जूस आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है**
  पसीना और नमी आपके स्कैल्प में बैक्टीरिया के विकास का कारण बन सकते हैं। यह बालों के रोम को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसकी वजह से आपको स्कैल्प में खुजली, रूसी और बालों का झड़ना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन आप नोनी फ्रूट जूस का सेवन करके, इसके जीवाणुरोधी और एंटीफंगल गुणों के कारण इसे कम कर सकते हैं।
- **यह थकान को कम करने के लिए जाना जाता है**
  थकान का प्रमुख कारण आयरन की कमी है, जिससे एनीमिया हो सकता है। नोनी फल आयरन का एक बड़ा स्रोत है, और इसीलिए यह गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए भी बहुत अच्छा है। तो, अब आप जानते हैं कि यदि आप ऊर्जा पर कम हैं तो आपको क्या चाहिए।
- **यूरिक एसिड को कम करता है**
  उच्च यूरिक एसिड बुजुर्गों में सबसे आम समस्याओं में से एक है। यह समस्या न केवल पूरी प्रतिरक्षा प्रणाली को बाधित करती है, बल्कि यह पूरी तरह से दर्दनाक भी है। अगर आपके घर में कोई ऐसा ही है, तो बिना समय बर्बाद किए उनकी डाइट में एक गिलास नोनी जूस शामिल करें और बदलाव देखें।
- **मानसून से संबंधित बीमारियों के लिए**
  मानसून बीमारियों के साथ आता है। खांसी, जुकाम, बदन दर्द, बुखार, दस्त आदि। लेकिन आप में से जो नोनी फल खा रहे हैं, उन्हें सुरक्षा मिलेगी। इसका कारण, इम्युनिटी है!

करेले में छुपे हैं ढेरों फायदे

कई ऐसी फल और सब्जियां हैं, जो हमारे लिए काफी गुणकारी हैं। ये हमें कई तरह की बीमारियों से बचाकर स्वस्थ और फिट रखती हैं। कई लोग इनके फायदों से इतने अवगत नहीं होते। अब करेले को ही लीजिए। कड़वेपन के कारण कई लोग करेला खाना पसंद नहीं करते हैं, जबकि करेले में हमारे लिए ढेरों फायदे छुपे होते हैं।

करेले के फायदों को देखते हुए सभी को करेले को प्रमुखता से अपने खानपान का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इसे सब्जी के रूप में और साथ ही जूस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जानते हैं करेले खाने से हमें कितने फायदे मिलते हैं।

करेला हर किसी की सेहत के लिए अच्छा होता है लेकिन लोग इसे खाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इसे खाकर लोग अक्सर कड़वा महसूस करते हैं। लेकिन करेला सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है इसलिए आपको इससे दूर नहीं भागना चाहिए बल्कि आपको इससे दोस्ती करनी चाहिए। और हर दिन इसे अपनी डाइट में शामिल करें ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे।

अगर आप करेले की सब्जी खाते हैं। तो ऐसे में आप जूस भी लें, इससे आपकी स्किन समस्या के साथ बालों और डायबिटीज को भी काफी फायदा मिलता है। करेले का जूस पीने से आपका चेहरा भी ग्लो करता है। साथ ही बॉडी अच्छे से डिटॉक्स हो जाती है जिससे वेट कंट्रोल होता है। करेला विटामिन सी से भरपूर होता है। ऐसे में जानें कैसे करेले के जूस का इस्तेमाल करें।

डायबिटीज में फायदे

डायबिटीज में करेला हमेशा फायदेमंद साबित होता है। इसमें इंसुलिन जैसा प्रोटीन होता है जिसे पॉलीपेप्टाइड पी कहा जाता है। इसके साथ ही ये डायबिटीज के ब्लड शुगर लेवल को कम करता है म्ये नेचुरल तरीके से आपके डायबिटीज को कम करता है, इसे खाली पेट पीएं।

लिवर के लिए फायदेमंद

करेले का जूस आपकी आंतो को साफ करता है, दरअसल जूस में मोमोर्डिका चाररेंटिया नामक एक तत्व पाया जाता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो लिवर को मजबूत करके लिवर डैमेज से सुरक्षा प्रदान करता है, ये आपके ब्लैडर के काम को भी बढ़ावा देता है।

मोटापा कम करे

करेले का जूस मोटापा कम करने में काफी मदद करता है। दरअसल करेले में कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है। जिससे कैलोरी कंट्रोल में होती है और वजन नहीं बढ़ता है म्आप करेले का जूस लेंगे तो इससे आपकी डिटॉक्स होता है, इसलिए आप वेट लॉस कर रहे हैं तो ऐसे में करेले का जूस जरुर पीएं।

स्किन के लिए अच्छा

करेले के जूस में विटामिन ए और सी जैसे शक्तिशाली एंटी-ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। जो आपकी स्किन को अच्छा बनाता है। इसके साथ ही ब्लड सर्कुलेशन में भी सुधार करता है। ये आपकी स्किन की और कई सारी परेशानियों का भी हल निकलता है।

हृदय के लिए

हृदय संबंधी परेशानियों में भी करेला फायदेमंद रहता है। यह हानिकारक वसा को हृदय की धमनियों में जमने नहीं देता जिससे रक्तसंचार सुचारू बना रहता है, और हार्ट अटैक की आशंका कम होती है। करेले की पत्तियों या फल को पानी में उबालकर इसका सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कई तरह का संक्रमण ठीक हो जाता है। वजन होगा कम करेले में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालते हैं। सुबह के समय करेले के रस में नींबू की कुछ बूंदें मिलाकर पी जाएं तो शरीर डीटॉक्स होता है। इसके अलावा करेला हमारे शरीर के मेटाबोलिज्म को बढ़ा देता है, जिससे पाचन सही रहता है और इन स्थितियों में वजन कम करना आसान हो जाता है।

आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है सुबह की खाली पेट चाय की चुस्की

अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं, जिनके लिए चाय एक एनर्जी ड्रिंक का काम करती है या फिर जिनकी सुबह ही एक कप गर्म प्याली चाय के साथ होती है तो यह खबर आपके लिए ही है। जी हां क्या आप जानते हैं खाली पेट सुबह की चाय की गर्म चुस्की आपकी सेहत पर कितना बुरा असर डाल सकती है। आइए जानते हैं।

सुबह खाली पेट चाय पीने से पेट में अम्लीय और क्षारीय पदार्थों के असंतुलन की वजह से चयापचय प्रणाली बाधित हो सकती है। यह शरीर की नियमित चयापचय गतिविधि में हस्तक्षेप करके व्यक्ति को दिन भर परेशान रख सकता है। एक अध्ययन के अनुसार, जब दूध को चाय के साथ मिलाया जाता है, तो दूध में मौजूद वजन घटाने के लिए जिम्मेदार तत्वों का असर कम हो जाता है। इसके अलावा दूध से बनी चाय पेट के एसिड को बढ़ाकर आपके पाचन तंत्र पर भी बुरा असर डाल सकती है। जो कि वजन बढ़ने का एक मुख्य कारण हो सकता है।

अल्सर की समस्या

अक्सर आपने कई लोगों को यह कहते सुना होगा कि उन्हें सुबह उठते ही एकदम स्ट्रॉन्ग और गर्मागरम चाय पीना पसंद है। पर क्या आप जानते हैं सुबह-सुबह खाली पेट गर्म चाय पीने से पेट की अंदरूनी हिस्से पर चोट लग सकती है, जो आगे चलकर पेट के अल्सर का कारण भी बन सकता है।

मोटापे की समस्या

खाली पेट चाय पीने से उसमें घुली हुई चीनी शरीर में प्रवेश करती है, जिससे व्यक्ति का वजन बढ़ने के साथ मोटापा भी बढ़ता है।

हड्डियों के लिए बुरी है चाय

खाली पेट लंबे समय तक रोज कई कप चाय के पीने से स्केलेटल फ्लोरोसिस जैसी बीमारी हो सकती है यह बीमारी हड्डियों को अंदर ही अंदर खोखला बना देती है। जिसकी वजह से कई गंभीर बीमारी भी हो सकती है।

थकान और चिड़चिड़ापन

ऐसा कहा जाता है कि चाय पीने से ताजगी आती है। हालांकि सच तो ये है कि सुबह दूध वाली चाय पीने से काम में थकान और चिड़चिड़ापन हो सकता है।

पाचन क्रिया पर बुरा असर

सुबह उठते ही कई लोग खाली पेट चाय पीने लगते हैं। जिसकी वजह से उनके पेट में गैस बनने के साथ उनकी पाचन क्रिया भी धीमी हो जाती है। खाली पेट चाय पीने से पित्त की प्रक्रिया में भी बाधा आती है। जिसकी वजह से मिचली और बेचैनी महसूस हो सकती है।

तनाव बढ़ने का है कारण

सुबह उठते ही फ्रेश और ऊर्जावान बने रहने के लिए लोग एक कप चाय पीना पसंद करते हैं। नतीजतन, ऐसे व्यक्तियों के शरीर में कैफीन की मात्रा काफी बढ़ जाती है और उन्हें नींद न आने के साथ तनाव और अवसाद जैसी समस्याएं घेर सकती हैं।

ह्रदय रोग का खतरा

खाली पेट चाय पीने से इसमें मौजूद कैफीन तेजी से शरीर में घुलने लगता है। जो व्यक्ति के ब्लड प्रेशर को प्रभावित करके दिल की सेहत पर भी बुरा असर डालता है।

इस तरह से पिएं चाय

अगर आप चाय के शौकीन हैं तो हमेशा न ही ज्यादा गर्म और न ही अधिक ठंडी चाय पीएं। सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है तो खाली पेट चाय पीने की जगह उसके साथ बिस्किट या स्नैक्स जरूर लें।

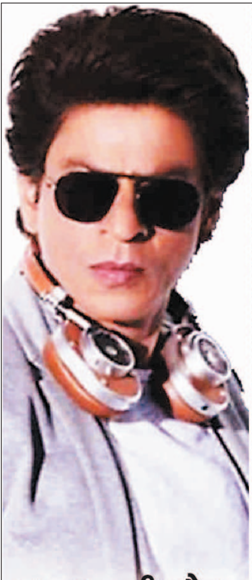

क्या एटली और शाहरुख खान फिर से करेंगे साथ में काम?

जवान 2 को लेकर सामने आई अपडेट

शाहरुख खान आज लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं और दुनिया भर में उनके लाखों फैन हैं। हाल ही में, शाहरुख ने 33 साल में अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। एटली की फिल्म जवान के बाद से फैंस इसके सीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फैंस चाहते हैं कि दोनों फिर साथ काम करें। अब एटली ने जवान 2 को लेकर नई अपडेट शेयर की है।

क्या बनेंगी जवान 2

एटली ने बताया कि जवान 2 जल्दी नहीं बनेगी, बल्कि कुछ साल बाद हो सकती है। लेकिन वे और शाहरुख किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर जरूर काम करेंगे। एटली ने शाहरुख को अपना पसंदीदा पिकलबॉल पार्टनर बताया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मैं और शाहरुख सर किसी प्रोजेक्ट पर जरूर काम करेंगे। लेकिन जवान 2 शायद कुछ साल बाद बनेगी। अभी तुरंत नहीं। जब मौका मिलेगा, तो हम इस पर सोचेंगे।

डॉन 3 के बारे में

एटली ने डॉन 3 निर्देशित करने की अफवाहों को झुठला दिया है। पहले खबर आई थी कि रणवीर सिंह के जाने के बाद शाहरुख फिर डॉन बनेंगे, लेकिन एटली ही निर्देशक होंगे। लेकिन एटली ने कहा, यह सिर्फ अफवाह है। मैंने भी पढ़ा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।

फिल्म जवान के बारे में

शाहरुख ने इसमें दोहरी भूमिका निभाई थी- एक सैनिक पिता और उसके पुलिस अधिकारी बेटे की। उनके डायलॉग और एक्शन की बहुत तारीफ हुई। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म जवान 2023 में रिलीज हुई थी। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में विजय सेतुपति और नयनतारा ने भी अभिनय किया है।

तेलुगु सिनेमा में डेब्यू के लिए तैयार राशा थडानी

बॉलीवुड में फिल्म आजाद से डेब्यू कर चुकी अभिनेत्री राशा थडानी अब तेलुगु सिनेमा में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। वह फिल्म श्रीनिवास मंगापुरम में नजर आने वाली हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म का मोशन पोस्टर सामने आ चुका है। सोशल मीडिया पर अपनी फिल्म का मोशन पोस्टर शेयर करते हुए राशा थडानी ने खुशी जाहिर की है। इसके साथ उन्होंने एक पोस्ट लिखी है। आइए जानते हैं इसमें क्या है?

राशा की फिल्म का मोशन पोस्टर

इंस्टाग्राम पर राशा थडानी ने जो पोस्टर शेयर किया है, उसमें देखा जा सकता है कि उन्होंने हल्की बैंगनी रंग की ड्रेस पहनी है। उन्होंने अपने बाल खोले हैं। इसके बैकग्राउंड में गुड़हल के फूल लगे हैं। मोशन पोस्टर शेयर करते हुए राशा थडानी ने लिखा है श्रीनिवास मंगापुरम की मंगा से मिलिए। आभार और उम्मीद से भरे दिल के साथ, मैं तेलुगु सिनेमा में अपना पहला कदम रख रही हूं। यह एक ऐसी दुनिया है, जहां जमीन से जुड़ी कहानियां होती हैं। इस सफर ने मुझे अपने ऊपर यकीन करना और सब्र करना सिखाया है। उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मुझ पर शुरुआत में भरोसा किया।

कौन है फिल्म का निर्देशक?

फिल्म श्रीनिवास मंगापुरम के निर्देशक अजय भूपति हैं। राशा थडानी इस फिल्म में मंगा का किरदार निभाएंगी। यह फिल्म कब रिलीज होगी इसके बारे में जानकारी नहीं है। अजय भूपति ने पहले आरएक्स 100, महा समुद्रम और मंगलावरम जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है।

राशा थडानी का करियर

आपको बता दें कि राशा थडानी ने फिल्म आजाद से बॉलीवुड में कदम रखा था। इसमें अजय देवगन के भतीजे अमन देवगन ने भी अभिनय किया था। फिल्म का निर्देशन अभिषेक कपूर ने किया था। 17 जनवरी 2025 को रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी। राशा जल्द ही फिल्म लइकी लइका में नजर आने वाली हैं। इसके अलावा वह तेलुगु सिनेमा में डेब्यू के लिए तैयार हैं।

'सैयारा' फेम अहान पांडे ने एक्टिंग की दुनिया में इस वजह से रखा कदम

पिछले साल अहान पांडे ने फिल्म 'सैयारा' से बॉलीवुड में कदम रखा था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही है। अहान को भी खूब फेम मिला। लेकिन एक्टर बनने से पहले अहान ने एक नहीं कई करियर अपने लिए चुने। आखिर में उन्होंने एक खास वजह से एक्टर बनने का फैसला किया।

डीजे से लेकर वीडियो गेम डिजाइन तक का किया काम

हाल ही की गई बातचीत में अहान पांडे ने बताया कि उन्होंने एक्टर बनने से पहले कई करियर चुने थे। वह कहते हैं, 'सोलह साल की उम्र में, मैंने डीजे का प्रोफेशनल ट्राई किया। फिर म्यूजिक प्रोडक्शन में हाथ आजमाया। मेरा एक ग्रुप था जिसका नाम 'बेस ट्रैप' था। इसमें हमने कुछ ट्रैक रिलीज किए। फिर मैं वीडियो गेम डिजाइन में आया।'

फिल्मी दुनिया में इस तरह रखा कदम

अहान पांडे आगे कहते हैं, 'आखिर में मैंने फिल्म सेट पर असिस्ट करना शुरू किया क्योंकि कहानी कहने का पैशन मेरे अंदर कहीं छुपा था। मैंने फिल्म सेट पर सब कुछ चुपचाप देखा। उसके बाद मैंने अपना पहला फिल्म ऑडिशन भी दिया। तब मुझे पता चला कि सही लोगों के सामने परफॉर्म करना कैसा लगता है? यहीं से मैंने तय किया कि मैं इसी एक चीज पर टिका रहूंगा। मजे की बात यह है कि इतनी सारी चीजें करने की चाहत ने मुझे सिखाया कि एक्टिंग क्यों परफेक्ट है। मुझे उन सभी चीजों को करने का मौका एक्टिंग में ही मिल जाता है।'

हम अच्छी फिल्में नहीं बना रहे

शाहिद कपूर ने बॉलीवुड के मौजूदा हालात पर दी प्रतिक्रिया

पिछले कुछ साल में इस बात पर बहस तेज हो गई है कि डूम स्क्रॉलिंग ने ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को कैसे प्रभावित किया है। कई लोगों का मानना है कि अब लोगों में लंबे समय तक चलने वाले मनोरंजन के लिए धैर्य नहीं बचा है। कुछ लोग तो इसे बॉलीवुड के पतन का एक कारण भी बताते हैं, क्योंकि दर्शक फिल्में देखने में कम रुचि दिखा रहे हैं। अब अपनी आगामी फिल्म 'ओ रोमियो' के प्रमोशन में जुटे अभिनेता शाहिद कपूर ने इस मुद्दे पर बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ कम ध्यान केंद्रित करने की क्षमता ही इंडस्ट्री के मौजूदा हालातों के लिए जिम्मेदार नहीं है। एक्टर ने बॉलीवुड में अच्छी फिल्मों की कमी पर भी बात की।

मेकर्स भी अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे

बातचीत में शाहिद कपूर ने कम ध्यान केंद्रित करने के मुद्दे पर कहा देखिए, मोमबत्ती दोनों तरफ से जल रही है। दर्शक अपना धैर्य खो रहे हैं। उनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है। उन्हें उत्तेजना चाहिए, उन्हें ब्रेक चाहिए, क्योंकि इससे डोपामाइन का स्तर बढ़ता है। मेकर्स भी अपने साथ ऐसा ही कर रहे हैं, इसलिए जब वे ध्यान केंद्रित करके काम करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी रचनात्मक क्षमता प्रभावित होती है। ऐसा नहीं है कि दर्शक फिल्में देखना नहीं चाहते; लेकिन हम उतनी अच्छी फिल्में नहीं बना पा रहे हैं जितनी बनानी चाहिए। इसलिए यह एक दोतरफा प्रक्रिया है।

मेन्यूफैक्चेट मार्केटिंग पर जताई नाराजगी

शाहिद ने मेन्यूफैक्चेट मार्केटिंग पर भी अपनी राय रखते हुए कहा कि लोग समझते नहीं हैं, लेकिन यह जीवन का एक चमत्कार है। जब लोगों से भरा एक कमरा ताली बजाता है, सीटी बजाता है और आपको पहचानता है, आपको अपने से ऊपर दर्जा देता है, तो यह बहुत खूबसूरत होता है। इसीलिए कला खास है। लेकिन जब वह पवित्रता भंग होने लगती है और उसमें बनावटीपन आ जाता है, तो उसका महत्व खत्म हो जाता है। मार्केटिंग तो हर किसी को करनी पड़ती है। लेकिन मार्केटिंग कब सही और गलत की सीमा पार कर जाती है? हद से ज्यादा क्या होता है? यह वास्तव में आपकी अपनी नैतिक समझ पर निर्भर करता है। अगर आप उस समझ के साथ काम करना चुनते हैं, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप सिर्फ बिजनेस और आंकड़ों के लिए काम कर रहे हैं, तो वह सिर्फ बिजनेस और आंकड़े ही हैं और वही आपका जीवन का अनुभव है। अगर आप कुछ प्रामाणिक, मानवीय, सहज खोज रहे हैं, तो उसे होने दें। उसे कंट्रोल करने की कोशिश न करें।

13 फरवरी को रिलीज होगी 'ओ रोमियो'

शाहिद कपूर जल्द ही विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित 'ओ रोमियो' में नजर आएंगे। मुंबई के गैंगस्टर हुसैन उस्तरा पर आधारित इस फिल्म में शाहिद कपूर के साथ तृप्ति डिमरी प्रमुख भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

इंडस्ट्री में कोई किसी का बेस्ट फ्रेंड नहीं

टेलीविजन की मशहूर शुभांगी अत्रे इन दिनों आगामी फिल्म भाबीजी घर पर हैं को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बीच अभिनेत्री ने इंडस्ट्री में फ्रेंडशिप को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। शुभांगी अत्रे ने कहा कि इस इंडस्ट्री में कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। अभिनेत्री ने हाल ही में बालाजी टेलीफिल्म्स के पॉपुलर पॉडकास्ट ऑनेस्टली, व्हाई नॉट? में स्पेशल गेस्ट के तौर पर शिरकत की थी। इस शो में होस्ट ने अभिनेत्री से मनोरंजन जगत में दोस्ती को लेकर सवाल किए। होस्ट ने पूछा था कि क्या आपने कभी इंटरव्यू में अपने को-स्टार्स के साथ सबसे अच्छे दोस्त होने को लेकर झूठ बोला है? इस सवाल का जवाब देते हुए अभिनेत्री ने कहा, देखिए, यहां पर कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, क्योंकि यहां पर लोगों में कॉम्पीटिशन और एक दूसरे को लेकर इंसीक्योरिटी बहुत ज्यादा है। जब एक शो चलता है, तब आप बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन जैसे ही आप उस शो से निकलते हैं, वो रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। फिर आप अपनी जिंदगी की एक नई यात्रा शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि एक एक्टर होने की सबसे अच्छी बात ये है कि आप खुद को लगातार खोजते और समझते रहते हैं। उन्होंने आगे कहा, इसलिए यहां बेस्ट फ्रेंड जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हां, इतना जरूर है कि जब तक हम साथ काम करते हैं, तब हम एक परिवार की तरह रहते हैं।

इसके बाद होस्ट ने पूछा, आपके साथ सेट पर कभी ऐसा हुआ है कि सीन करने के बाद आपकी किसी के साथ नोकझोंक या लड़ाई हो गई और फिर से उन्हीं के साथ सीन करना पड़ रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे करना ही नहीं है? इस सवाल का जवाब शुभांगी अत्रे ने हंसते हुए दिया। उन्होंने कहा कि वे अपने काम को काफी पसंद करती हैं और जब किरदार में रहती हैं तो वे सब भूल जाती हैं।

पहले जिस टैग से भागती थी अब वो खुशी देता है

भूमि पेडनेकर की वेब सिरीज 'दलदल' सिर्फ एक क्राइम-थ्रिलर कहानी नहीं है, बल्कि इसमें बचपन हुए ट्रॉमा पर भी बात की गई है। बातचीत में भूमि ने फिल्म में दिखाए गए वॉयलेंस और उसे दिखाने के उद्देश्य पर चर्चा की। इसके अलावा एक्ट्रेस ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी काफी कुछ साझा किया।

पिछले साल बॉक्स ऑफिस पर मेल एक्शन और वॉयलेंस ट्रेंड में रहा। ऐसे माहौल में आपकी सीरीज का वॉयलेंस कहां खड़ा होता है?

सीरीज में वॉयलेंस है, लेकिन मैं इसे महिला बनाम पुरुष के नजरिए से नहीं देखती। मेरे लिए वॉयलेंस का कोई जेंडर नहीं होता। असली बात यह है कि कहानी में वॉयलेंस दिखाया क्यों जा रहा है ? यहां वॉयलेंस सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि किरदारों की मनोवैज्ञानिक हालत और उनके भीतर के ट्रॉमा को समझाने के लिए है। जब किसी के अंदर इतनी घुटन हो तो प्रतिक्रिया भी तीखी ही होगी। ऐसे में दलदल का वॉयलेंस मुझे जरूरत के मुताबिक लगता है न कि बनावटी।

क्या पर्सनल लाइफ में कभी कोई दर्दनाक अनुभव हुआ?

जी हां। हम सबकी जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जो भीतर एक तरह का ट्रॉमा छोड़ जाता है। यह हमेशा बहुत बड़ा नहीं होता। कभी बचपन में कोई बुरा अनुभव हो जाए, कोई बैड टच हो, या स्कूल में किसी ने बुली कर दिया हो। उस समय हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी उस अनुभव को याद रखती है। वह याद हमारे शरीर में कहीं न कहीं दर्ज हो जाती है। औरत होने के नाते अगर कभी आपको खतरा महसूस हुआ हो, कोई आपको दूर से घूरता रहा हो, या किसी की मौजूदगी ने आपको असहज कर दिया हो, तो वह भी ट्रॉमा ही है।

कठिन अनुभवों से बाहर आने में आपकी सबसे बड़ी ताकत कौन रहा?

कठिन अनुभवों से बाहर आने में मेरे परिवार ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं खुद को बहुत लकी मानती हूं कि मेरे पास ऐसा परिवार है। स्कूल के दिनों में भी मेरे साथ कुछ बातें हुईं, लेकिन मैं हमेशा अपने माता पिता के पास जा सकती थी। वे मजबूती से मेरे साथ खड़े रहे। मुझे पता था कि वे बिना जज किए मुझे समझेंगे और संभालेंगे।

आपको अक्सर सामाजिक मुद्दों वाली फिल्मों से जोड़ा जाता है। क्या यह टैग आपको सीमित करता है?

हां, मेरी फिल्मों में अक्सर सामाजिक मुद्दे दिखाई देते रहे हैं और कुछ समय तक मुझे इस बात का डर भी था कि कहीं मुझे सिर्फ सामाजिक विषयों वाली फिल्मों का टैग न मिल जाए। पहले यह सवाल मुझे थोड़ा परेशान कर देता था क्योंकि लगता था कि शायद लोग मुझे एक ही तरह की फिल्मों में देखने लगेंगे। लेकिन आज मैं इस बात पर गर्व महसूस करती हूं। पहले मैं इस टैग से भागती थी पर अब मुझे एहसास है कि यह एक तरह की जिम्मेदारी भी है और मुझे वह जिम्मेदारी निभाने में खुशी होती हैमैं ऐसे ही काम करना चाहती हूं। मुझे कंटेंट आधारित और सामाजिक रूप से जागरूक फिल्में करना पसंद है ऐसी कहानियां जिनमें कोई सार्थक बात हो... जो किसी की सोच को बदल सकें या कम से कम प्रभावित कर सकें। अगर मेरा काम किसी की सोच को थोड़ा भी आगे बढ़ा सके तो मेरे लिए यही सबसे बड़ा पुरस्कार है।

किस तरह के किरदार और निभाने की इच्छा है?

मैं एक पीरियड फिल्म करना चाहूंगी। मैंने अब तक कोई पीरियड फिल्म नहीं की और मैं हमेशा से इस जोनर के प्रति बेहद आकर्षित रही हूं। हमारे इतिहास में कई महान औरतें, नेता और नायिकाएं रही हैं जिनके बारे में जानकर लगता है कि उन किरदारों को निभाना कितना प्रेरणादायक होगा। स्वतंत्र भारत या उससे पहले के दौर की किसी मजबूत महिला पर आधारित कहानी में काम करना मुझे बहुत पसंद आएगा।

इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए कौन सा बदलाव देखना चाहेंगी?

मैं हमेशा पे गैप के बारे में बात करती हूं क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए पे गैप अब भी बहुत ज्यादा है। खासकर पोस्ट पैंडेमिक इसका असर और भी बढ़ गया है और उसका पूरा बोझ औरतों को ही झेलना पड़ा है।मैं सच में उम्मीद करती हूं कि इसमें कुछ बराबरी आए। साथ ही मुझे लगता है कि महिलाओं के नेतृत्व वाली कहानियों को थिएटर में जितना स्पेस और अवसर मिलना चाहिए उतना अब नहीं मिल रहा। यह धीरे-धीरे कम होता जा रहा है।यह बदलाव सिर्फ इंडस्ट्री अपने आप नहीं ला सकती इसमें ऑडियंस की भी बड़ी भूमिका है। अगर ऑडियंस ऐसे कंटेंट को सपोर्ट करे तो महिलाओं के नेतृत्व वाली कहानियों को फिर से वह जगह मिल सकती है जिसकी वे हकदार हैं।

छोटे वाहनों और बसों के लिए वैकल्पिक मार्ग व पार्किंग व्यवस्था निर्धारित, यातायात सुचारू रखने हेतु नागरिकों से सहयोग की अपील

दुर्ग जिले में कल भारी वाहनों का शहर में प्रवेश रहेगा पूर्णत : प्रतिबंधित

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

दुर्ग जिले में 6.फरवरी को छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का सम्मेलन आयोजित किया जाना है। सम्मेलन के दौरान जिले में वीवीआईपी एवं वीआईपी मूवमेंट प्रस्तावित है। आम नागरिकों की सुविधा, सुरक्षा एवं सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा विशेष यातायात डायवर्शन प्लान लागू किया गया है।

छोटे वाहनों के लिए रूट

ग्रीन चौक दुर्ग से राजनांदगांव जाने वाले वाहन अग्रसेन चौक, इंदिरा मार्केट, पटेल चौक, गंजपारा, पुलगांव चौक, राजेन्द्र पार्क-चर्च गेट, चौपाटी टर्निंग, उतई तिराहा, जेल रोड, महाराजा चौक होकर आवागमन करेंगे। सेक्टर क्षेत्र से दुर्ग शहर में प्रवेश करने वाले वाहन ठगड़ा बंध पुल से होकर जेल तिराहा, समृद्धि मार्केट, साईं द्वार, राजेन्द्र पार्क मार्ग का उपयोग करेंगे।

शेप ब्रिज दुर्ग से पुलगांव की ओर जाने वाले वाहन मालवीय नगर, राजेन्द्र प्रसाद चौक, चर्च चौपाटी टर्न, साईं द्वार, कासिरिडीह, जेल तिराहा, महाराजा चौक, पद्मनाभपुर मार्ग से होकर जाएंगे।

दुर्ग जिले में वीवीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर विशेष यातायात डायवर्शन प्लान सम्मेलन के दौरान दुर्ग शहर में वीवीआईपी/वीआईपी मूवमेंट प्रस्तावित

बसों के लिए रूट व पार्किंग

दुर्ग से रायपुर, बेमेतरा, कवर्धा, गंडई, सलहेवारा, रेंगाखार जाने वाली बसें धमधा ओवरब्रिज के पहले गंज मंडी स्थित FCI गोदाम में पार्क होंगी तथा क्रमवार सवारी लेकर रवाना होंगी। दुर्ग से राजनांदगांव, खैरागढ़, बालोद, डोंगरगढ़, दल्लीराजहरा, धमतरी, अर्जुंदा जाने वाली बसें पुलिस लाइन दुर्गझगंजपारा में पार्किंग कर जीवन प्लाजा के सामने से सवारी लेंगी। दुर्ग से पाटन, रानीतरई, धमतरी जाने वाली बसें महिला समृद्धि बाजार, सिविल लाइन दुर्ग के सामने पार्किंग कर वहीं से प्रस्थान करेंगी।

दुर्ग पुलिस की अपील

यातायात पुलिस दुर्ग आम नागरिकों से अपील करती है कि निर्धारित डायवर्शन मार्गों, बस पार्किंग एवं स्टैंडिंग व्यवस्था का पालन करें, यातायात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का सहयोग करें तथा अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित मार्गों का उपयोग न करें। आपके सहयोग से यातायात व्यवस्था सुरक्षित एवं सुचारू बनी रहेगी। इस सम्मेलन में ओबीसी वर्ग से जुड़े लोगों के बड़ी संख्या में शामिल होने की संभावना है।

खास खबर

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव : बिजली उपभोक्ताओं और सेवानिवृत्त कर्मियों का हुआ सम्मान

दुर्ग। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, दुर्ग क्षेत्र के अंतर्गत नगर संभाग पश्चिम भिलाई द्वारा कोहका स्थित रुंगटा कॉलेज (आर-वन) के सभागार में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 2026 का गरिमामय आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जनप्रतिधियों, विभागीय अधिकारियों और बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन, भिलाई नगर निगम के सभापति गिरवर बंटी साहू, पार्षद श्रीमती अंजू सिन्हा और रामानंद मौर्य उपस्थित रहे। साथ ही जनप्रतिनिधि अजय साहू, सुमन सागर सिन्हा सहित विभिन्न वार्डों के पार्षदगणों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

सभागार परिसर में बिजली विभाग की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं को बैनर और प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। विभाग के अधिकारियों ने उपस्थित जनसमूह को शासन की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी, ताकि अधिक से अधिक लोग इनका लाभ उठा सकें।

रजत महोत्सव के विशेष अवसर पर विभाग ने अपने निष्ठावान उपभोक्ताओं और अनुभवी कर्मियों का सम्मान किया। कार्यक्रम में घरेलू, गैर-घरेलू, कृषि, बीपीएल श्रेणी और पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत आने वाले उत्कृष्ट उपभोक्ताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। विभाग की लंबी सेवा कर चुके सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कमर्चारियों को पुष्पगुच्छ और पौधे भेंट कर उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में अधीक्षण अभियंता जे. जगन्नाथ प्रसाद एवं एस. मनोज, कार्यपालन अभियंता नवीन राठी सहित समस्त सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता और स्टाफ का विशेष योगदान रहा।

क्रिकेट टीम के लिए चयन स्पर्धा का आयोजन

भिलाई। बोकारो स्टील प्लांट द्वारा 10 से 14 फरवरी तक बोकारो में आयोजित की जा रही एस.पी.एस.बी. अंतर इस्पात संयंत्र क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र की वरिष्ठ क्रिकेट टीम के गठन हेतु क्रीड़ा, सांस्कृतिक एवं नागरिक सुविधाएं विभाग द्वारा दिनांक 05 फरवरी, 2026 को दोपहर 2:00 बजे से बीएसपी क्रिकेट ग्राउंड, इंदिरा प्लेस में चयन स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। इस चयन स्पर्धा में भाग लेने के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र के नियमित कार्मिक खिलाड़ी तथा भिलाई परिधीय क्षेत्र के प्रतिभागी पात्र होंगे। इच्छुक प्रतिभागी दिनांक 05 फरवरी, 2026 को दोपहर 1:30 बजे तक चयन स्थल पर उपस्थित होकर निम्नलिखित चयनकर्ताओं के समक्ष अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं— सुरेश सोनपिपरे, सुरेश बाबू, मोहन दास। उप प्रबंधक (क्रीड़ा, सांस्कृतिक एवं नागरिक सुविधाएं) अभिजीत भौमिक इस चयन स्पर्धा के प्रभारी होंगे।

करोड़ों का बकाया, वेतन अधर में, ईंधन तक के पैसे नहीं

कर्ज, कुप्रबंधन और कागजी बैठकों में ही उलझा भिलाई नगर निगम

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

'आदर्श टाउनशिप' से 'आर्थिक बदहाली' तक का सफर

छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र और कभी 'आदर्श औद्योगिक टाउनशिप' के रूप में पहचाना जाने वाला नगर पालिक निगम भिलाई आज गंभीर आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि निगम के पास न तो कर्मचारियों को समय पर वेतन देने के पैसे हैं, न ही वाहनों में ईंधन भरवाने की राशि। नतीजा यह है कि सफाई, पानी सप्लाई, शवदाह गृह और परिवहन जैसी मूलभूत सेवाएं लगातार प्रभावित हो रही हैं।

ईंधन के पैसे नहीं, गाड़ियाँ खड़ी — करोड़ों का बकाया सूत्रों के मुताबिक निगम पर पेट्रोल पंपों का करोड़ों रुपये का बकाया है, जिसके चलते कई बार निगम वाहनों को ईंधन मिलना बंद हो जाता है। बीते दिनों में पेट्रोल पंप द्वारा शव वाहनों को भी डीजल नहीं दिया गया, इससे कचरा संग्रहण, पानी टैंकर और अन्य सेवाएं ठप पड़ जाती हैं। हाल ही में भुगतान के अभाव में कई गाड़ियाँ गैराज में खड़ी रहीं, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। सवाल यह भी है कि

अधिकारियों की गाड़ी में डीजल कैसे मिल रहा है अधिकारियों के गाड़ी में डीजल का संकट क्यों नहीं आ रहा है क्या सिर्फ लोगों के उपयोग में आने वाली वाहनों में ही डीजल संकट है या अधिकारियों के वाहनों में भी।

मुक्तिधाम में लकड़ी संकट, परिजनों की मजबूरी

निगम की बदहाल व्यवस्था का सबसे संवेदनशील उदाहरण मुक्तिधामों में लकड़ी की कमी है। कई बार स्थिति ऐसी बन चुकी है कि शवदाह गृह में लकड़ी खत्म हो जाती है और शोक संतप्त परिजनों को बाहर से महंगे दामों पर लकड़ी खरीदनी पड़ती है। यह न सिर्फ प्रशासनिक विफलता है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं पर भी सीधा प्रहार है।

50 करोड़ सफाई टेंडर से लेकर खरीद घोटाले तक

नगर निगम भिलाई लगातार विवादों में घिरा रहा है— करीब 50 करोड़ के सफाई टेंडर की पारदशिर्ता पर सत्ता पक्ष के पाषर्दों ने भी सवाल उठाए कचरा ट्रॉली और सीसीटीवी कैमरों की खरीद में बाजार भाव से कई गुना अधिक भुगतान लाखों रुपये के संभावित घोटाले की आशंका, इन मामलों ने निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं।

वेतन संकट: कर्मचारी सड़कों पर

नगर निगम अपने ही कमर्चारियों को समय पर वेतन नहीं दे पा रहा है। सफाई कर्मियों को महीनों तक भुगतान नहीं मिलने से वे कई बार निगम कार्यालय का घेराव कर चुके हैं। यह स्थिति प्रशासनिक असंवेदनशीलता को उजागर करती है।

पानी, सफाई और प्रशासन तीनों चरमराए

आज स्थिति यह है कि— पानी सप्लाई कई बार पूरी तरह ठप, सफाई व्यवस्था अव्यवस्थित, निविदा प्रक्रियाओं में विवाद, गर्मियों में जल संकट, अतिक्रमण हटाने में जन आक्रोश हर समस्या पर बैठक होती है, समीक्षा होती है, चिंतन होता है— लेकिन निष्कर्ष कभी नहीं निकलता।

BSP से अरबों का टैक्स विवाद

भिलाई स्टील प्लांट और निगम के बीच 5 अरब से अधिक के प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर मामला अदालत में लंबित है। जब तक यह विवाद नहीं सुलझता, निगम की आय पर संकट बना रहेगा।

विवादों ने बढ़ाया संकट

निगम की आय बढ़ाने के प्रयास भी विवादों में उलझ गए हैं— निर्यात कर विवाद, भिलाई प्रदेश का इकलौता निगम है जो उद्योगों से 'निर्यात कर' मांग रहा है। करीब 193 उद्योगों पर 42 करोड़ बकाया बताया जा रहा है, जिसका उद्योग जगत विरोध कर रहा है।

क्यों नहीं सुधरती व्यवस्था? सबसे बड़ा सवाल

सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि— क्या निगम में जवाबदेही की कमी है? क्या अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों में समन्वय नहीं? क्या भ्रष्टाचार और लापरवाही व्यवस्था को खोखला कर रही है? बार-बार वही समस्याएं, वही वादे, वही फाइलें—और हालात जस के तस।

चेतावनी की घंटी या आखिरी मौका?

नगर पालिक निगम भिलाई आज जिस मोड़ पर खड़ा है, वह सिर्फ आर्थिक संकट नहीं, बल्कि प्रशासनिक विफलता का प्रतीक बन चुका है। यदि समय रहते ठोस सुधार नहीं किए गए, तो यह संकट आने वाले दिनों में शहरवासियों के लिए और भी गंभीर रूप ले सकता है। अब जरूरत है— पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन, जवाबदेह प्रशासन, ठोस निर्णय, और राजनीतिक इच्छाशक्ति की वरना 'आदर्श औद्योगिक नगरी' कहलाने वाला भिलाई, कुप्रबंधन का उदाहरण बनकर रह जाएगा।

वार्षिक उत्सव में इंद्रजीत सिंह ने विद्यार्थियों का बढ़ाया उत्साह

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

नेशनल एकेडमी स्कूल, रिसाली रोड धनौरा, भिलाई में आयोजित वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में सर्व समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी के डायरेक्टर इंद्रजीत सिंह एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अमनदीप कौर विशेष रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय परिवार, शिक्षकों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों को कार्यक्रम की सफलता पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही समाज के विकास की सबसे मजबूत नींव है और बच्चों को सकारात्मक दिशा देने में विद्यालयों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के दौरान सर्व समाज कल्याण समिति के महासचिव मलकीत सिंह, उपाध्यक्ष जोगा राव, शाहनवाज कुरैशी, रमन राव, वाजिद अंसारी, सुनील यादव सहित स्कूल प्रबंधन के पदाधिकारी, समिति सदस्य एवं बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे।

कुरूद में बहनों की बैठक में स्वावलंबन पर दिया सहयोग का भरोसा

कुरूद में बहनों की बैठक में सुनी समस्याएं, दिया सहयोग का आश्वासन इसी क्रम में कुरूद स्थित ढांचा भवन में आयोजित स्थानीय बहनों की आवश्यक बैठक में भी श्री इंद्रजीत सिंह ने सहभागिता की। बैठक के दौरान महिलाओं ने स्वावलंबन, रोजगार और आत्मनिर्भरता से जुड़े विषयों पर अपनी समस्याएं एवं सुझाव रखे। इंद्रजीत सिंह ने सभी बातों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए बहनों को यथासंभव सहयोग, सहायता एवं उचित मार्गदर्शन प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं का आत्मनिर्भर होना समाज को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम है और इस दिशा में हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

राख में बदलने के बजाय देहदान का निर्णय, चोपड़ा दंपत्ति ने किया चिकित्सा शिक्षा के लिए दान

नई दृष्टिबिंदु / खैरागढ़

कहते हैं कि इंसान जीते-जी जितना दूसरों के काम आता है, उतना ही बड़ा पुण्य वह मृत्यु के बाद भी कमा सकता है। इसी सोच को साकार किया है, खैरागढ़ नगर के गोलबाजार निवासी दंपत्ति ने, जिन्होंने अपने शरीर को राख में बदलने के बजाय चिकित्सा शिक्षा के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया है।

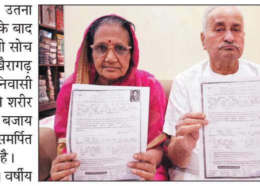

चोपड़ा परिवार के 71 वर्षीय किशन चोपड़ा और उनकी 67 वर्षीय पत्नी पुष्पा देवी चोपड़ा ने मृत्यु उपरांत देहदान का निर्णय लेकर समाज के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। दंपत्ति ने राजनांदगांव स्थित अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय के शरीर रचना शास्त्र विभाग में देहदान की औपचारिक प्रक्रिया पूरी कर ली है।।

उनका उद्देश्य स्पष्ट है—मृत्यु के बाद भी उनका शरीर चिकित्सा छात्रों की शिक्षा में उपयोगी बने और भावी डॉक्टरों के निर्माण में योगदान दे सके। किशन चोपड़ा ने बताया कि देहदान की इच्छा उन्हें स्वयं के भीतर से उत्पन्न हुई। जब उन्होंने इस विषय पर अपनी पत्नी से चर्चा की, तो पुष्पा देवी ने भी सहमति जताई।

इसके बाद पुत्र और दोनों पुत्रियों से विचार-विमर्श किया गया, जिन्होंने माता-पिता के इस निर्णय को गर्व के साथ समर्थन दिया।

BJP के नए 'कप्तान' नितिन नवीन की टीम का काउंट-डाउन शुरू, मध्य प्रदेश के इन 8 दिग्गजों को 'दिल्ली' बुलाने की तैयारी!

नई दृष्टिबिंदु / नई दिल्ली-भोपाल

भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बहुत जल्द अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान करने जा रहे हैं। 45 वर्षीय युवा अध्यक्ष के कमान संभालने के बाद से ही भाजपा के केंद्रीय संगठन में बड़े बदलावों की आहट है। सूत्रों की मानें तो नितिन नवीन की इस 'नई भाजपा' में मध्य प्रदेश के नेताओं का दबदबा देखने को मिल सकता है।

संगठन के लिहाज से भाजपा के सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाले एमपी से कई चेहरों को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। संभावित नामों को लेकर गहराई से पड़ताल की, तो यह सामने आया कि टीम चयन में जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन और 'परफॉरमेंस' को आधार बनाया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान के केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बाद, अब संगठन में एमपी से नए चेहरों को एडजस्ट करने की कवायद तेज है।

इन चेहरों पर लग सकती है मुहर (संभावित नामों की एक्सक्लूसिव सूची): वी.डी. शर्मा मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले वी.डी. शर्मा का कद बढ़ना तय माना जा रहा है। संघ (RSS) और एबीवीपी की मजबूत पृष्ठभूमि वाले शर्मा को राष्ट्रीय महामंत्री जैसी अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनकी संगठनात्मक क्षमता का उपयोग पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहती है।

नरोत्तम मिश्रा

पार्टी के फायरब्रांड नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद, उनकी वाकपटुता और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उनकी पहचान उन्हें केंद्रीय संगठन के लिए उपयोगी बनाती है। वे विपक्ष पर हमलावर रहने वाले नेताओं में गिने जाते हैं।

कैलाश विजयवर्गीय

राष्ट्रीय राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी कैलाश विजयवर्गीय पहले भी राष्ट्रीय महामंत्री रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर हरियाणा तक चुनावी प्रबंधन का उनका अनुभव उन्हें फिर से टीम नितिन नवीन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना सकता है।

लाल सिंह आर्य

वतर्मान में एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सक्रिय लाल सिंह आर्य के काम से केंद्रीय नेतृत्व संतुष्ट बताया जा रहा है। उन्हें मुख्य संगठन में प्रमोट किया जा सकता है या उन्हें मोर्चा में ही और बड़ी भूमिका दी जा सकती है।

फग्गन सिंह कुलस्ते

क्यों हैं रेस में: आदिवासी समुदाय के बड़े और अनुभवी नेता हैं। कई बार केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं। पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए संगठन में किसी बड़े आदिवासी चेहरे को शामिल करना चाहती है, जिसमें कुलस्ते का दावा सबसे मजबूत है।

कविता पाटीदार

क्यों हैं रेस में: वतर्मान में राज्यसभा सांसद हैं। वे ओबीसी वर्ग से आती हैं और एक महिला नेता हैं। नितिन नवीन की 'युवा टीम' के कॉन्सेप्ट में कविता पाटीदार बिल्कुल फिट बैठती हैं। वे मालवा क्षेत्र में संगठन में लंबे समय से सक्रिय हैं और उन्हें राष्ट्रीय मंत्री या प्रवक्ता जैसी जिम्मेदारी मिल सकती है।

सुमित्रा वाल्मीकि

क्यों हैं रेस में: राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि दलित समुदाय से आती हैं और जमीनी स्तर से ऊपर उठी हैं। महिला और वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के कारण, पार्टी उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लाकर 'सबका साथ, सबका विकास' के नारे को और मजबूत कर सकती है।

डॉ. हितेश वाजपेयी

क्यों हैं रेस में: मध्य प्रदेश में पार्टी का मुखर चेहरा और सीनियर प्रवक्ता हैं। मीडिया डिबेट्स में पार्टी का पक्ष मजबूती से रखने के लिए जाने जाते हैं। नितिन नवीन अपनी नई टीम में आक्रामक संचारकों को जगह देना चाहते हैं, ऐसे में डॉ. वाजपेयी को राष्ट्रीय प्रवक्ता या मीडिया विभाग में अहम रोल मिल सकता है।

राजनीतिक मायने:

नितिन नवीन की यह टीम मिशन 2029 का रोडमैप तैयार करेगी। ऐसे में मध्य प्रदेश के इन अनुभवी और ऊर्जावान नेताओं का समावेश संगठन को नई धार देने का काम करेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि अंतिम सूची में इनमें से किन-किन नेताओं की लॉटरी लगती है।

नारायणपुर मैराथन से लौटी जसोदा सिक्का को सम्मानित किया वकीलों ने

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

अधिवक्ता जसोदा सिक्का ने नारायणपुर मैराथन में हिस्सा लेकर पांचवा स्थान हासिल किया। उन्हे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हाथों दस हजार रुपए नगद इनाम दिया गया। उनके दुर्ग आगमन पर दुर्ग में अधिवक्ताओं ने शुभकामनाएं दी और सम्मान किया।

जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग की पहल पर दुर्ग पहुंची जसोदा सिक्का का संघ के पूर्व अध्यक्ष गुलाब सिंह पटेल ने पुष्पगुच्छ देकर तथा मुंह मीठा करवाकर स्वागत किया। संघ के अन्य सदस्यों में नरेन्द्र सोनी, उत्तम चंदेल, संतोष वर्मा, बादशाह प्रसाद सिंह (सदस्य स्टेट बार काउंसिल) संघ के पूर्व उपाध्यक्ष- फारूख भाई, संघ के पूर्व कोषाध्यक्ष- मनोज मून अमोद पाठक, आलोक सारस्वत, प्रभात पाण्डेय, अशोक यादव, हर्ष दुबे, निशा सिंह, आंचल, काजल मिश्रा, आकांक्षा जायसवाल, सविता पाध्येय, रेखा दुबे, मंदीप सिंह, जया श्रीवास्तव, नंदिनी चंद्रवंशी, पूनम मांझी, अनामिका, सारिका, अविनाश वर्मा, दीपक यावलकर, चंदनराय अल्तमश फारूकी, जे.पी. साहू, सलील दीपेन्द्र देशमुख, प्रशांत दुबे, एस.एन. पाण्डे, नर्सिंग शर्मा, ललित सेन, प्रेमनारायण साहू, पी.आर. सार्वा, चेतन लाल उके, घनश्याम साहू आदि अधिवक्ताओं ने भी उनका स्वागत किया। अधिवक्ताओं ने संघ को गौरवान्वित करने वाली उपलब्धि के साथ उन्हे महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया।

पीआरजीआई सं.-CTHIN/25/A3746 यह हिंदी सांध्य दैनिक समाचार पत्र नई दृष्टिबिंद स्वामी एवं प्रकाशक आलोक तिवारी द्वारा समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 से मुद्रित करवा कर। 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से प्रकाशित संपादक आलोक तिवारी मो. 7415469100 (समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार), समस्त विवादों का निपटारण न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।